

संक्षिप्त समाचार

टिंकू शुक्ला स्लेक मेन और उनकी टीम का आभार



जांजगीर (समय दर्शन)। जो हर दिन कम से कम 10 साँपों का रेस्क्यू करते हैं किसी भी जगह से फेन आने पर चाहे दूरी कितनी भी हो वो अपने निजी काम को दरकिनार कर कोई भी किसी भी समय साँपों का रेस्क्यू करते हैं कभी कभी तो आधी रात को जाते हैं उनकी सोच है कि साँपों की वजह से किसी भी व्यक्ति या बच्चे महिला पुरुष को हानि न हो और साथ ही साथ साँपों को भी सुरक्षित जगह में छोड़ते हैं अनुराग टिंकू शुक्ला जाँजगीर निवासी का सुरु से जानवरों के प्रति अपने भावनाएं प्रगट करते रहे हैं में उनका आभार करता हु ?

शासकीय प्राथमिक शाला देव किरारी में न्योता भोज का आयोजन किया गया



जांजगीर (समय दर्शन)। अकलतरा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अपील पर पुरे प्रदेश में न्योता भोज का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा अभिनय पहल चलाया जा रहा है जिसके तहत शासकीय प्राथमिक शाला देव किरारी विगत वर्ष कक्षा पांचवी में अध्यनरत छात्राएं कुमारी प्रियांगो साहू पिता सत्यम साहू एवं कुमारी सिंह साहू पिता अनिल कुमार साहू के जवाहरलाल नवोदय विद्यालय में चयन होने की खुशी की उपलक्ष में न्योता भोज कार्यक्रम रखा गया। सभी के द्वारा न्योता भोज को बहुत सराहा गया। "स्कूल में बच्चों को नेवता भोज कराया" से संबंधित समाचार का तात्पर्य है कि स्कूल में बच्चों के लिए विशेष भोज का आयोजन किया जाना। यह आयोजन किसी खास मौके, जैसे कि नए सत्र की शुरुआत, किसी त्योहार, या किसी अन्य विशेष अवसर को मनाने के लिए किया जा सकता है। इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य बच्चों को खुश रखना, उनके बीच सामूहिकता की भावना विकसित करना और उन्हें विशेष अवसरों पर सम्मानित महसूस करना होता है ताकि स्कूल के प्रति रूचि रहे और शिक्षा प्राप्त करने हेतु तत्पर रहें। नेवता भोज में बच्चों ने इस आयोजन का आनंद लिया, उनके लिए विशेष भोजन तैयार किया गया जिसमें शिक्षण समिति के अध्यक्ष कमल कश्यप, लक्ष्मी वर्मा, सत्यम साहू एवं समस्त स्टाफ छात्राएं सम्मिलित हुए।

सैमसंग ने नये फोल्डेबल फोन गैलेक्सी Z फोल्डप6 और Z फिलप6 को लॉन्च किया, गैलेक्सी एआई को नई ऊंचाईयों पर पहुंचाया

पेरिस। सैमसंग ने आज पेरिस में गैलेक्सी अनपैकड कार्यक्रम में गैलेक्सी बड्स3 और गैलेक्सी बड्स3 प्रो के साथ अपने बिल्कुल नए गैलेक्सी Z फोल्ड 6 और गैलेक्सी Z फिलप 6 को लॉन्च किया है। नई गैलेक्सी Z सीरीज की शुरुआत के साथ, सैमसंग गैलेक्सी एआई के नए अध्याय को सामने ला रहा है। इसके लिए उपभोक्ताओं को शानदार अनुभव देने के लिए डिजाइन किए गए सबसे बेहतरीन और मजबूत फॉर्म फैक्टर का लाभ उठाया जाएगा। गैलेक्सी एआई कन्प्यूटेशन, प्रॉडक्टिविटी और क्रिएटिविटी के एक नए युग को गति देने के लिए मजबूत, इंटीग्रेटेड और टिकाऊ फोल्डेबल अनुभव को साथ लाता है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल एक्सपीरिएंस बिजनेस के प्रेसिडेंट और हेड टीएम रो ने कहा, इनोवेशन के लंबे इतिहास ने सैमसंग को मोबाइल क्षेत्र में नैतिक बनाने, फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर बनाने और मोबाइल एआई युग की शुरुआत करने में सक्षम बनाया है। अब, हम इन दो टेक्नोलॉजीज को एक साथ लाने और दुनिया भर के यूजर्स के लिए नई संभावनाओं का दरवाजा खोलने जा रहे हैं। हमारे फोल्डेबल प्रॉडक्ट्स प्रत्येक यूजर्स की उसकी अनूठी जरूरतों को पूरा करते हैं और अब यह गैलेक्सी एआई की शक्ति के साथ अनूठा अनुभव देने जा रहा है।

32सूत्रीय मांग को लेकर पटवारी काम बंद, कलम बंद बेमुद्दत हड़ताल पर

बसना (समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ अपने 32 सूत्रीय मांगों को लेकर बेमुद्दत हड़ताल पर जा चुके हैं। बसना तहसील कार्यालय परिसर में छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ बसना, सरायपाली और पिथौरा के पटवारी ऑनलाइन एप भुइयों में गड़बड़ी, संसाधनों की कमी समेत 32 सूत्रीय मांगों को लेकर चौथे दिन भी काम बंद-कलम बंद अतिशक्तिशाली हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पटवारियों के हड़ताल पर चले जाने से राजस्व विभाग का कामकाज पूरी तरह से ठप्प हो चुका है। जिससे ग्रामीण, किसान और छात्र काफी परेशान हो रहे हैं। इसकी वजह से जनता की मुसीबत बढ़ गई है। अभी के समय में बच्चों को शालेय गतिविधियों के लिए आय जाति निवास आदि प्रमाण पत्र की नितान्त आवश्यकता पडती है। वहीं कृषि आधारित कार्यों के संचालन के लिए किसान भाईयों का भी पटवारी प्रथम स्थानीय अधिकारी होता है। देखा जाय तो ग्रामीण स्तर के सभी शासकीय कार्य पटवारी से प्रारंभ होता है। पटवारियों के हड़ताल से जन सामान्य, छात्र एवं किसानों के सभी कार्य अवरुद्ध हो गये हैं। इधर पटवारियों के हड़ताल को समर्थन देने स्थानीय कांग्रेस नेता धरना स्थल पहुंचे। पटवारियों का कहना है कि सरकारी ऑफिस में ऑनलाइन कामों के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर जैसी चीजों की सुविधा ही नहीं है। पटवारियों का आरोप है कि, ऑनलाइन कार्य के लिए शासन द्वारा किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। अलावा इसके, आवश्यक संसाधन और नेट भला भी नहीं दिया जा रहा है। पटवारियों की सरकार से शिकायत है कि, उन्हें जरूरी सुविधाएँ नहीं दिए जा रहे हैं। ऑनलाइन नक्शा, बटाकन में संशोधन सीधे पटवारी की आईडी से होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हो रही है। जिला स्तर पर सहायक प्रोग्रामरों की पदस्थापना की जानी चाहिए। साथ ही, भूमि खरीद-बेच में रजिस्ट्री के साथ ही भुइयां पोर्टल पर भी इसे अपडेट किया जाना चाहिए।



इसके, आवश्यक संसाधन और नेट भला भी नहीं दिया जा रहा है। पटवारियों की सरकार से शिकायत है कि, उन्हें जरूरी सुविधाएँ नहीं दिए जा रहे हैं। ऑनलाइन नक्शा, बटाकन में संशोधन सीधे पटवारी की आईडी से होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हो रही है। जिला स्तर पर सहायक प्रोग्रामरों की पदस्थापना की जानी चाहिए। साथ ही, भूमि खरीद-बेच में रजिस्ट्री के साथ ही भुइयां पोर्टल पर भी इसे अपडेट किया जाना चाहिए।

किसान भाईयों का कर्ज लेने बैंक में काट लेने के बाद भी भुइयां पोर्टल में बंधक नहीं हटाया जाता है, उसे स्वतः हटाने का प्रावधान होना चाहिए। पटवारियों की हड़ताल से सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के किसानों, छात्रों को परेशान होना पड़ रहा है। जरूरी दस्तावेज बनाने के लिए किसान और छात्र तहसीलों के चकर काट रहे हैं, लेकिन पटवारियों के नहीं होने से राजस्व का कामकाज पूरी तरह अटक पडा है। इधर स्थानीय कांग्रेस नेता पटवारियों के समर्थन में उनके मांगों को जायज बताते हुए समर्थन में खड़े हो गये हो गये हैं। **भाजपा सरकार पटवारियों के मांग को शीघ्र पूर्ण करे-कांग्रेस :** ब्लाक कांग्रेस कमटी बसना कांग्रेसी नेता मनजीत सिंह सलूजा, इस्तिफाक खेरा की सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ तहसील कार्यालय परिसर पहुंचकर पटवारियों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि, छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय की भाजपा सरकार पटवारियों की पीड़ा को समझते हुए जल्द उनको सभी मांगों को पूरा करने की मांग की है।

जीवनदीप समिति की बैठक में मरीजों के हित में कई निर्णय

निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा से चार माह में 7 हजार से ज्यादा मरीज लाभान्वित

बिलासपुर (समय दर्शन)। जिला अस्पताल के जीवन दीप समिति की कार्यकारिणी की बैठक जिला कलेक्टर अरविश शरण की अध्यक्षता में जिला अस्पताल में संपन्न हुई। अस्पताल में मरीजों की सुविधा बढ़ाने के लिए कई निर्णय लिए गए। बैठक में बताया जिला अस्पताल में निःशुल्क एक्स रे एवं सोनोग्राफी सुविधा दिये जाने का गत चार माह में 7187 गरीब मरीजों को लाभ मिला है। इससे 4 लाख रुपये से ज्यादा की राशि गरीब परिवारों की बचत हुई है। जीवन दीप समिति की आज की बैठक में विचार-विमर्श करने के बाद मरीज के परिजनों हेतु वाशरूम एवं कपड़ा सुखाने की व्यवस्था, दो नये मोटर पम्प की स्वीकृति, 10 नग नये अग्निशमन यंत्र खरीदने, पानी टंकियों को आपस में जोड़ने, आयुष्मान योजना के तहत मल्टी स्कैनर प्रिन्टर एवं यूपीएस की खरीदी, एनक्व्यूएस, मुस्कान और लक्ष्य सर्टिफिकेशन के लिए गेप को पूरा करने को पूरा करना, नगर निगम द्वारा स्थापित आरओ प्लाण्ट की मरम्मत, सोनोग्राफी कक्ष के लिए कामर्शियल बैटरी खरीदी, सीसीटीव्ही कैमरा, पाकिंग शेड क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना हेतु भूमि आवंटन सहित अस्पताल में सुविधाओं को उन्नत करने के लिए कई निर्णय लिये गये। सिविल सर्जन ने समिति की आय-व्यय विवरण का अनुमोदन किया गया। पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों का पालन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर ने मदिरापान कर अस्पताल आने वाले लोगों और चोरी की घटना पर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ रामप्रसाद चौहान, सीएमएचओ डॉ. प्रताप श्रीवास्तव, सिविल सर्जन डॉ अनिल गुप्ता सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं जीवनदीप समिति के सदस्य उपस्थित थे।



बैठक में लिये गये निर्णयों का पालन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर ने मदिरापान कर अस्पताल आने वाले लोगों और चोरी की घटना पर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ रामप्रसाद चौहान, सीएमएचओ डॉ. प्रताप श्रीवास्तव, सिविल सर्जन डॉ अनिल गुप्ता सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं जीवनदीप समिति के सदस्य उपस्थित थे।

कलेक्टर ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण

सीसीयू सहित अन्य सुविधाओं के लिए किया स्थल चिन्हांकन हमर लैब एवं बर्न यूनिट का निर्माण दस दिनों में पूर्ण करने निर्देश



बिलासपुर (समय दर्शन)। कलेक्टर अरविश शरण ने आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में जनसुविधाओं के विस्तार एवं इन्हें व्यवस्थित करने अधिकारियों को निर्देश दिए। अस्पताल के आस-पास की भूमि की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। गौरतलब है कि सरकार ने राज्य में एकमात्र जिला अस्पताल बिलासपुर के लिए 75 बेडयुक्त क्रिटिकल केयर यूनिट स्थापना की स्वीकृति दी है। इसके निर्माण के लिए 10 हजार वर्गफीट भूमि की जरूरत है। कलेक्टर ने अस्पताल परिसर का

भ्रमण कर भूमि का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला अस्पताल में पिछले दो साल से बंद पड़े वाटर एटीएम को एक सप्ताह में चालू करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. अनिल गुप्ता, हॉस्पिटल कंसल्टेंट डॉ. शोफली, रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला समन्वयक श्री सौरभ सक्सेना, नगर निगम के जल प्रभारी श्री अनुपम तिवारी, जीवन दीप समिति के सदस्य अमित सिंह सहित अधिकारी गण उपस्थित थे।

जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाले समस्याओं तथा उनके रोकथाम के बारे में दी गई जानकारी



"विश्व जनसंख्या दिवस" महासमुंद्र (समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार तथा स्टेट प्लान आफ एक्शन के तहत आज 11 जुलाई "विश्व जनसंख्या दिवस" के अवसर पर माननीय न्यायाधीशों द्वारा विभिन्न स्कूलों तथा गांवों में जाकर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस तारतम्य में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के

अधिकारों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इसके अलावा गुड टच बेड टच, बाल श्रम कानून, माता पिता वरिष्ठ भरण-पोषण अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, पीडित क्षतिपूर्ति योजना आदि विषयों पर छात्र-छात्राओं को जानकारी दी गई। उन्होंने नालसा एव 'सालसा तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों तथा उससे मिलने वाले विधिक सलाह एवं सहायता के विभिन्न योजनाओं के बारे में बताते हुए बताया कि पात्र व्यक्ति किसी कानूनी सहायता एवं सलाह की आवश्यकता पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क कर निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार तालुका स्थित न्यायालयों के न्यायाधीशों विधिक जागरूकता पर आधारित शिविर का आयोजन किया गया।

पटवारीयों द्वारा जारी 32 सूत्रीय मांगों का शिवसेना ने किया समर्थन

गंददास मानिकपुरी (सिटी रिपोर्टर)

महासमुंद्र (समय दर्शन)। शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह ठाकुर ने पटवारीयों के धरना स्थल पहुंचकर पटवारीयों द्वारा जारी 32 सूत्रीय मांगों का समर्थन किया, धर्मेन्द्र सिंह ठाकुर ने अपने उद्बोधन में कहा कि पटवारीयों द्वारा जटिल परिस्थितियों में भी संयम से कार्य किया जाता रहा है, मोर भुइयों साफ्टवेयर में जटिल त्रुटियों के चलते आन लाइन त्रुटियां हो रही हैं जिसके चलते गांव-गांव में असंतोष की स्थिति है और उस स्थिति में भी पटवारियों को वर्षों से कार्य करना पड़ा, लेकिन अब स्थिति अनियंत्रित होने लगी है जिस कारण पटवारीयों को अपनी मांगों को लेकर धरना में बैठना पड़ा है।



ठाकुर ने आगे कहा कि स्थानीय पुलिस द्वारा बिना जांच के पटवारीयों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और पटवारीयों की हड़ताल से किसान, विद्यार्थी, आम जनता के कार्य प्रभावित हो रहे हैं और पटवारियों की मांगे जायज हैं, शासन-प्रशासन द्वारा अभी तक इस गंभीर विषय में ध्यान न देना दुर्भाग्यजनक है और शासन-प्रशासन द्वारा त्वरित पटवारियों की जायज मांग को पूर्ण करनी चाहिए। समर्थन के दौरान शिवसेना के जिलाध्यक्ष अजय बंजारे, युवासेना जिलाध्यक्ष नीरज साहू, हरि चतुर्वेदी, बादल बंजारे, दुर्गेश गुप्ता, धीरज सिन्हा, हेमन्त साहू, आदि शिव सैनिक भी उपस्थित थे। ठाकुर द्वारा ठेकेदार यूनियन के जिलाध्यक्ष होने के नाते भी ठेकेदार यूनियन की ओर से पटवारियों के हड़ताल का समर्थन किया गया।

दरबार मोरवली जनसमस्या निवारण शिविर में 255 आवेदन निराकृत

विभिन्न विभागों के हितग्राही मूलक योजना से 37 हितग्राही लाभान्वित, सांसद विजय बघेल शामिल हुए जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में

पाटन (समय दर्शन)। ग्रामीण जनता की समस्याओं को सुनने, समझने और समाधान के लिए आम जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम दरबार मोरवली में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित की गई। कलेक्टर सुश्री त्रिभुवा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में जिला प्रशासन के समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी सम्मिलित हुए और विभाग को ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों का मौके पर निराकरण किये। शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 407 आवेदन प्राप्त हुए। जिसमें से 255 आवेदनों का निराकरण किया गया, शेष 152 आवेदनों के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई। शिविर में विभिन्न विभागों के हितग्राही मूलक योजना से 37 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। सांसद श्री विजय बघेल भी इस जिला स्तरीय शिविर में शिरकत किये। शिविर में कृषि, उद्यानकी,



पशुपालन, मत्स्य, श्रम, खाद्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, सहकारिता, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य, जल संसाधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा विभागीय योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कलेक्टर सुश्री चौधरी की मौजूदगी में विभागवार प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने प्राप्त आवेदनों का मौके पर संबंध में आवेदकों को अवगत कराये। शिविर में जिला पंचायत के अधिकारियों ने जिले में जल संरक्षण को बढ़ावा देने नारी शक्ति से जल शक्ति व जल मडुई के महत्व को प्रदर्शित किया। शिविर का शुभारंभ छत्तीसगढ़ महतारी के तैल चित्र पर माल्यापर्ण एवं समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कलेक्टर सुश्री त्रिभुवा प्रकाश चौधरी ने विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण कर प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। साथ ही

अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के साथ गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। सांसद श्री विजय बघेल ने भी विभागीय स्टॉलों का अवलोकन कर अधिकारियों से रू-ब-रू चर्चा तथा विभागीय योजनाओं के क्रियावन्धन की जानकारी ली। मुख्य अतिथि की आसंदि से शिविर के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए सांसद श्री विजय बघेल ने कहा कि जनसमस्या निवारण शिविर सरकार के नए कार्यकाल में पुरानी व्यवस्था का पुनः शुरुवात है। जिले में

करने की सख्त निर्देश दिए। सांसद श्री बघेल ने आवेदकों को भी विनम्र भाव से अधिकारियों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने कहा है। सांसद ने जिला प्रशासन के जल संरक्षण अभियान व जल मडुई की सराहना की। शिविर को सम्बोधित करते हुए कलेक्टर सुश्री चौधरी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप यह आयोजन किया जा रहा है। सभी जिला प्रमुख अधिकारी जनता की समस्याओं का समाधान करने पहुंचे हैं। आवेदन जिस कडीशन में प्राप्त हुए हैं, निराकरण का पूरा प्रयास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिविर का लक्ष्य पूरा करने जनता का सहयोग भी जरूरी है। जिला पंचायत सदस्य श्रीमती हर्षा चंद्राकर ने भी शिविर के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये। मुख्य अतिथि सांसद श्री विजय बघेल ने अपने करकमलों से विभिन्न विभागों के हितग्राही मूलक योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को सामग्री प्रदान

सार समाचार
लोहे का चैनल लेकर ट्रक चालक फरार

रायपुर (समय दर्शन)। सरोरा स्थित महामाया स्टील कंपनी से लाखों रुपए का लोहे का चैनल लेकर ट्रक चालक फरार हो गया। प्रार्थी की शिकायत पर उरला पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ अमानत में ख्यात का मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी अफजल अंसारी 40 वर्ष पारस नगर देवेन्द्र नगर का रहने वाला है। प्रार्थी ने थाना में शिकायत किया कि वाहन क्रमांक आरजे 52 वीए 8322 के चालक ने सरोरा के महामाया स्टील से 14,33,708 रुपए के लोहे का चैनल लोड कर कर्नाटक के लिए रवाना हुआ था, जो आज तक अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाया।

फर्जी कंपनी बनाकर ठगी, जुर्म दर्ज

रायपुर (समय दर्शन)। अज्ञात व्यक्ति ने प्रार्थी का आईडी कार्ड प्राप्त कर 2 कंपनियों के नाम से फर्म बनाकर ठगी किया। प्रार्थी की शिकायत पर आमामानाका पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी मनीष कुमार पाठक 37 वर्ष एएस अस्पताल टाटीबंध के पास रहता है। बताया जाता है कि अज्ञात आरोपी ने प्रार्थी के आधार कार्ड, पेनकार्ड प्राप्त कर दो कंपनी आईसा इंटरप्राइजेस एवं पाठक इंटरप्राइजेस के नाम से धोखाधड़ी किया।

गांजा के साथ एक युवक गिरफ्तार

रायपुर (समय दर्शन)। विधानसभा पुलिस ने गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आमामामानाका पुलिस ने आरोपी जलधर दीप 28 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से 1 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त किया है।

प्लांट के अंदर कैटिन कर्मी हुआ बेहोश

रायपुर (समय दर्शन)। भिलाई इस्पात संयंत्र के भीतर स्थित ब्लॉस्ट फर्नेस वर्क आफिस बिल्डिंग के ऊपर स्थित कैटिन में कैटिन कर्मचारी कार्य करते हुए गिर गया और बेहोश हो गया, जिसे उपचार के लिए मेन मेडिकल पोस्ट ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार कैटिन कर्मचारी लोकनाथ गिलास धोते समय गिरकर बेहोश हो गया था। उसके नीचे गिरते ही यहाँ हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने किसी तरह उसे संभाला और उसे तत्काल मेडिकल पोस्ट भेजा जहाँ उसका उपचार किया गया।

केन्द्रीय विद्युत तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ में हो रहे कार्यों की समीक्षा की राज्य और केन्द्र सरकार के बेहतर समन्वय से छत्तीसगढ़ का होगा तेजी से विकास : केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल

छत्तीसगढ़ जल्दी ही वापस आएगा 'पावर सरप्लस स्टेट' का दर्जा : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर (समय दर्शन)। केन्द्रीय विद्युत तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज अपने रायपुर आवास के दौरान छत्तीसगढ़ में ऊर्जा तथा शहरों में आवास व जनसुविधाएं विकसित करने किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में आयोजित बैठक में कहा कि राज्य और केन्द्र सरकार के बेहतर समन्वय से छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा। छत्तीसगढ़ में बिजली और आवास से संबंधित सभी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए भारत सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में अनेक सुधारवादी कदम उठाए जा रहे हैं। जनआकांक्षाओं के अनुरूप काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री अरूण साव, केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य



राज्य मंत्री तोखन साहू और मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बैठक में कहा कि लोगों को सस्ती और पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने केन्द्र सरकार द्वारा अनेक अनुदान योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं हैं। उन्होंने राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा दी जा रही सभी निधियों और अनुदानों का पूर्ण उपयोग करने को कहा। राज्य

में जिस तेजी से काम होंगे, उसी तेजी से भारत सरकार द्वारा राशि जारी की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य में विकास योजनाओं को लेकर केन्द्र सरकार की ओर से कोई कटिनाई नहीं आएगी। दोनों बेहतर समन्वय से काम करेंगे। केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बैठक में सुझाव दिया कि क्लिनी सिटी के तहत रायपुर को मिली 100 बसों का उपयोग नया रायपुर और रायपुर के बीच चलाने के लिए भी कर सकते हैं। उन्होंने विद्युत

विभाग के अंतर्गत लाइन-लॉस को कम करने के लिए किए जा रहे कार्यों, स्मार्ट मीटर की स्थापना, विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में विद्युतीकरण और बिजली उत्पादन के लिए कोयला की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने आवासन एवं शहरी कार्यों के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम ई-बस सेवा, स्मार्ट सिटी मिशन और राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन के कार्यों की समीक्षा की।

वृद्ध सुमरिता बाई को हर माह मिलेगा निःशुल्क राशन एस आर प्रा लि उरला द्वारा बंधक बनाकर जान से मारने की धमकी देकर सभी चल अचल संपत्ति पर कब्जा

मुख्यमंत्री साय ने बुनियादी सुविधा से जुड़े विषयों पर त्वरित कार्रवाई के लिए प्रशासन को दिए निर्देश

रायपुर (समय दर्शन)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आम जनता के राशन कार्ड जैसी बुनियादी सुविधाओं के आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। इसके चलते प्रशासन की कोशिश है कि न्यूनतम समय में राशन कार्ड के लिए आए आवेदकों के आवेदन पर कार्रवाई हो। जनदर्शन में आ रहे ऐसे आवेदनों पर त्वरित निराकरण हो रही है। सुमरिता बाई के अंत्योदय राशन कार्ड के लिए दिए गए आवेदन पर भी इसी तरह शीघ्र कार्रवाई की गई। कोरबा जिले के विकासखंड कटधोरा के ग्राम पंचायत अरदा की आवेदिका



सुमरिता बाई ने कलेक्टर जनदर्शन में आकर आवेदन दिया। कलेक्टर अजीत वसंत ने खाद्य अधिकारी को तत्काल निर्देशित किया कि पात्र सुमरिता बाई को अंत्योदय राशन कार्ड बनाकर दिया जाए। आवेदन पर त्वरित कार्रवाई कर सुमरिता बाई के नाम पर अंत्योदय राशन कार्ड जारी करारक ग्राम पंचायत के

सरपंच के माध्यम से घर में दिया गया। इसी तरह ग्राम जोरहाडबरी विकासखण्ड पाली निवासी प्रवीण कुमार ने अपनी माता के नाम पर जारी राशन कार्ड में स्वेच्छा से अपना नाम विलोपित करने जनदर्शन में आवेदन दिया। कलेक्टर के निर्देश के पश्चात खाद्य अधिकारी ने प्रवीण कुमार का नाम

आश्रित सदस्य से तत्काल विलोपित कर दिया। उल्लेखनीय है कि अंत्योदय अन्न योजना गरीब परिवारों के लिये मार्च, 2001 से जारी राशन कार्ड में स्वेच्छा से अंतर्गत अति गरीब परिवारों को 1 रुपए प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल प्रति परिवार, प्रतिमाह प्रदाय किए जाने का प्रावधान है।

एस आर प्रा लि उरला द्वारा बंधक बनाकर जान से मारने की धमकी देकर सभी चल अचल संपत्ति पर कब्जा

रायपुर (समय दर्शन)। सोनू कुमार द्वारा आज प्रेस वार्ता ली गई जिसमें सोनू कुमार ने बताया कि पिछले छे साल से एच एस आर प्रा लि उरला में आफिस इंचार्ज के पद पर कार्यरत था इस दौरान प्रशांत खेतान अंकित चौधरी एवं अभिषेक चौधरी के द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है और प्रताड़ित किया जा रहा है मेरी निजी जमीन पर कब्जा कर डरा धमकाकर फर्जी रजिस्ट्री करा ली गई है प्रशांत खेतान एवं अभिषेक के द्वारा अंकित चौधरी की कार क्र नं 04 ऋ 5022 में मुझे बंधक बनाकर हनुमान इस्पात से नूतन इस्पात ले जा कर मार पीट की गई मेरा चल अचल संपत्ति अपने कम्पनी के नाम



वाले कंपनी में भेज कर सारा ज्वेलरी अपने कब्जे में कर लिया दिनांक 13/06/2024 को उसके बाद में पूछा की मेरी सम्पत्ति लेने के बाद ट्रेडर्स वाले को पैमेंट बाकि है वो मेरे सम्पत्ति से आपको मिल गया चूँकि माल तिल में गया है इसको किस तरीके से पेमेंट सो करवाईया तो बोले की जो छोटा बील वाला है उसे कैश रसीव दिखा का किलयर कर लेंगे एवं श्री राम ट्रेडर्स वाले को पैमेंट सो करवा दिया और मेरे अकाउंट न. कोडक महिंद्रा बैंक में टोटल 7,15,000/ सात लाख पंद्रह हजार भेजे जिसका उपयोग इन लोगों ने मेरे द्वारा गोल्ड ज्वेलरी लोन लिया हआ लोन कंपनी को करके मेरा सारा गोल्ड ज्वेलरी आपने आदमियों को मेरे साथ लोन देने

छत्तीसगढ़ में खंड वर्षा ने बढ़ाई लोगों की चिंता

रायपुर (समय दर्शन)। प्रदेश में रूक-रूककर हो रही खंडवर्षा ने जहां कृषकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, तो वहीं आमजन भी आधी-अधूरी बारिश व तेज गर्मी व उमस से बेहाल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून आने के बावजूद उतनी बारिश नहीं हुई, जितनी होनी चाहिए। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में 28 फीसदी कम बारिश हुई है। इस वजह से प्रदेश के कई डैम सूखने की कगार पर हैं। इस बीच मौसम विभाग ने 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जबकि, इसके उलट 8 जिलों में बारिश न के बराबर होगी। विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में अभी तक 207 मिमी बारिश हो चुकी है, जबकि इसे अभी तक 286.7 मिमी होना चाहिए था। चंद्रशेखर ऋतु - धूल: यात्री बस में गांजा की तस्करी, 1 गिरफ्तार वहीं इस कमजोर मानसून और कम बारिश का सबसे ज्यादा असर प्रदेश भर के जलशयों में देखने को मिल रहा है। पिछले बीस दिनों में प्रदेश के जलाशयों में महज 3 फीसदी जलभरव हो सका है। आषाढ़ के मौसम में भी इतनी कम बारिश ने किसानों के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच दी है। पिताहाल जितनी वर्षा हुई है उससे राज्य के बड़े बांधों के हालात में सुधार होता नहीं दिखा रहा है। इस तरह प्रदेश के बांधों में जल भंडारण महज 34 फीसदी ही रह गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वियना पहुंचने पर भारतीय समुदाय द्वारा स्वागत किया गया।



जल्द होगा साय कैबिनेट का विस्तार

रायपुर (समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में जल्द ही फेरबदल हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद 15 जुलाई तक राज्य में कैबिनेट विस्तार किया जा सकता है। विष्णुदेव साय की कैबिनेट में अभी दो विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र से पहले सीएम साय अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। सीनियर नेता बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से ही राज्य में कैबिनेट विस्तार को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 15 जुलाई तक 2 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम दिल्ली का दौरा करेंगे। यहां पांच प्रमुख नामों में से किसी दो को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। मंत्रिमंडल के विस्तार में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा। विष्णुदेव साय की कैबिनेट में राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, अजय चंद्रकार, भावना बोहरा और गजेंद्र यादव में से किसी दो विधायकों को शामिल किया जाने की चर्चा है। वहीं यदि पुराने मंत्री हटाए जाते हैं तो फिर बस्तर को भी और प्रतिनिधित्व मिलना तय माना जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद माना जा रहा है कि रायपुर से एक नया मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में सीनियर नेता राजेश मूणत का नाम सबसे आगे है। राजेश मूणत, रमन सिंह की भी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर किसानों को सुगमता से मिल रहा है खाद-बीज

किसानों को अब तक 8.61 लाख मीट्रिक टन खाद और 7.85 लाख

रायपुर (समय दर्शन)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर प्रदेश के किसानों को उनकी मांग के अनुरूप सुगमता के साथ प्रमाणित खाद-बीज का वितरण किया जा रहा है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा इन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश के किसानों को अब तक 8.61 लाख मीट्रिक टन खाद जो लक्ष्य का 63 प्रतिशत वितरित हो चुका है। इसी प्रकार किसानों को 7.85 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 80 प्रतिशत है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में मानसून की बौछारों के साथ शुरू हुए खेती-किसानी में बोनी का रकबा भी निरंतर बढ़ते जा रहा है। राज्य में अब तक 23.02 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में



विभिन्न फसलों की बोनी हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा इस खरीफ सीजन में 48.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बोनी का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 08 जुलाई 2024 की स्थिति में प्रदेश में अब तक 200.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 1236 मिमी है। अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष खरीफ 2024 के लिए प्रदेश में 9.78 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 9.04 लाख क्विंटल बीज का भंडारण कर अब तक 7.85 लाख क्विंटल बीज का वितरण किसानों को किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 80 प्रतिशत है। इसी प्रकार प्रदेश में इस खरीफ सीजन में 13.68 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का

लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त लक्ष्य के विरुद्ध 12.80 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में भंडारण किया गया है। उक्त भंडारण के विरुद्ध 8.61 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किसानों को किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 63 प्रतिशत है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश के किसानों को सुगमता से उनकी मांग के अनुरूप खाद-बीज सुगमता से उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। खाद-बीज वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही सोसायटियों में पर्याप्त खाद-बीज का भण्डारण कर सतत निगरानी करने को कहा है।

अलग-अलग जगह से दो दोपहिया वाहन पार

रायपुर (समय दर्शन)। शहर के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों से अज्ञात चोर ने दो नग दोपहिया वाहन पार कर दिया। मामले में पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार तेलीबांधा निवासी निशा नथानी 35 वर्ष ने राजेन्द्र नगर थाना में शिकायत किया कि वह अपनी सूजुकी एक्ससे क्रमांक सीजी 04 एमवी 2133 को महावीर नगर चर्च के पास खड़ी किया था, तभी अज्ञात चोर ने पार कर दिया। चोरी गए मोपेड की कीमत करीब 30 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। वहीं दूसरे मामले में खन्हारडीह थाना में प्रार्थी इंद्र तांडी 25 वर्ष ने शिकायत किया कि वह अपनी बाइक क्रमांक सीजी 04 एएएन 0874 को अपने घर के बाहर खड़ी किया था, तभीह अज्ञात चोर ने पार कर दिया। चोरी गए बाइक की कीमत करीब 10 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

संपादकीय

टीएमसी सांसद को तगड़ा झटका

दिल्ली हाई कोर्ट से तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले को तगड़ा झटका लगा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी को मानहानि के मामले में कोर्ट ने उन्हें पचास लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया है। लक्ष्मी संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक सचिव हैं। अदालत ने माफीनामा प्रमुख अंग्रेजी अखबार में छपवाने और इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर पोस्ट करने को भी कहा है, जो छह माह तक नजर आना चाहिए। लक्ष्मी की याचिका के अनुसार गोखले ने 2021 में 13 और 23 जून को पुरी दंपति पर 2006 में स्पिटजरलैंड में काले धन से घर खरीदने की बात कही थी। गोखले द्वारा पोस्ट किया गया था कि स्विस् बैंक खातों और विदेशी काले धन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन की जांच करे। अदालत ने वादी के खिलाफ आगे भी कोई अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोका है। साथ ही, उनकी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की भरपाई कोर्ट भी राशि नहीं कर सकते की बात भी कही है। फिलवक्त लक्ष्मी पुरी किसी औपचारिक भूमिका में नहीं हैं परंतु उनकी निजी उपलब्धियों और राष्ट्र सेवा पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। हालांकि अदालती कार्यवाही के दौरान साकेत गोखले अपने रुख पर कायम रहे। कहना गलत नहीं होगा कि साक्ष्य मौजूद होने पर ही उन्हें सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह के आरोप लगाने थे। खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताते वाले गोखले राहुल गांधी से प्रभावित रहे हैं पर कांग्रेस से 2019 में उन्होंने संबंध तोड़ लिया था। क्राउड फंडिंग द्वारा जुटाए गए पैसों की हेराफेरी के आरोपों में 2022 में गोखले को गुजरात पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के शिकंजे में भी वह आ चुके हैं। दागदार छवि के बावजूद साकेत गोखले दूसरों के चरित्र पर कीचड़ उछाल कर अपने पद की गरिमा को भी चुटहिल कर रहे हैं। रही बात राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की तो उसका भी तो कोई स्तर होना चाहिए। राम मंदिर के खिलाफ और प्रधानमंत्री की अधोषिप संपत्ति जैसे मामलों पर याचिकाएं लगा कर सिर्फ विवाद उत्पन्न करना राजनेता को शोभा नहीं देता। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को भी अपने इस प्रवृत्त पर सख्ती करनी चाहिए। इससे उनके दल की छवि भी कम धूमिल नहीं होती। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, उच्च सदन का सदस्य होने के बावजूद मानहानि का हक नहीं मिल सकता।

क्या चाहता है चीन

चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की शंघाई सहयोग संगठन की अस्ताना बैठक में LAC पर गतिरोध खत्म करने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने 'सीमा पर शांति' बनाने पर सहमति जताई है। कजाकिस्तान के अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान चीन और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत को एक पॉजिटिव संकेत तो माना जा सकता है, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की ठोस उम्मीद के लिहाज से देखा जाए तो उसके लिए अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है।

बैठक की अहमियत : पहली बात तो यह कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात इस बीच जरूर हुई है, लेकिन उनकी बैठक एक साल बाद हो रही थी। बैठक की सार्थकता इस बात में भी है कि पहली बार दोनों पक्षों ने महसूस किया, LAC पर गतिरोध का लंबा खिंचना किसी के हक में नहीं है और यह कि 'सीमा पर शांति हमेशा बनानी पड़ती है।' इस लिहाज से दोनों पक्षों में इस बात पर भी सहमति बनी कि कूचीतिक और सैन्य अधिकारियों की मीटिंग जारी रखी जाए।

गतिरोध बरकरार : देखा जाए तो मई-जून 2020 में सीमा पर कई इलाकों में चीनी सेना के आगे बढ़ आने और गलवान घाटी में भिड़ंत होने के बाद तनावों के बीच भी दोनों पक्षों में बातचीत जारी रही। ऋष पर बने गतिरोध को खत्म करने के लिए वर्किंग मेकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की दो दर्जन से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं। कोर कमांडो लेवल पर भी 21 दौर की बातचीत हो चुकी है। कुछ मसले सुलझे भी हैं। लेकिन डेपसांग और डेमचक जैसे पॉइंट पर मतभेद बने हुए हैं, जिसकी वजह से सीमा पर दोनों ओर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती बरकरार है।

किना गंभीर है चीन : सवाल है कि क्या चीनी पक्ष इस बात को लेकर सचमुच गंभीर है कि बातचीत का कोई हल भी निकलें। संदेह की वजह यह भी है कि उसकी तरफ से पिछले कुछ समय से लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सीमा पर जो भी मतभेद हैं उन्हें दरकिनार करते हुए दोनों देशों को आपसी संबंध सामान्य बनाने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। इस पर भारत अपना रुख साफकर चुका है और उस पर अडिग है कि जब तक सीमा पर जारी गतिरोध को दूर नहीं कर लिया जाता तब तक दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हो ही नहीं सकते।

असल मंशा : ऐसे में दोनों विदेश मंत्रियों का यह स्वीकार करना कि 'सीमा पर शांति हमेशा बनानी पड़ती है', इस बात का संकेत माना जा सकता है कि अब दोनों पक्षों में होने वाली बातचीत को फ्लप्रद बनाने का अतिरिक्त प्रयास दोनों सरकारों की ओर से होगा। लेकिन यह संभावना सच होती है या नहीं और चीन अब सचमुच सीमा पर गतिरोध खत्म करना चाहता है या इस बैठक का मकसद अंतरराष्ट्रीय हलकों में कुछ खास संकेत देने तक सीमित था, यह आगे के उसके व्यवहार से ही स्पष्ट होगा।

धर्मोन्मूलन पर न्यायालय की चिन्ता और सरकार की उदासीनता

मनोज ज्वाला

खबर है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय अनुसूचित जातीय-जनजातीय एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को क्रिश्चियनिटी अथवा इस्लाम में तब्दील किए जाने के व्यापक रिलीजियस-मजहबी अभियान चिंता जताते हुए कहा है इसे यदि रोका नहीं गया तो देश की बहुसंख्यक आबादी शीघ्र ही अल्पसंख्यक हो जाएगी या मुसलमान और तब देश की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी; अतएव सरकार कठोर कानून बना कर इस अभियान पर तत्काल रोक लगावे। ऐसी ही चिंता पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय भी जता चुका है। हालांकि दोनों ही न्यायालयों ने इसे 'ईसाईकरण' अथवा 'इस्लामीकरण' की संज्ञा देते हुए ऐसा कहा है, किन्तु मेरा मानना है कि यह धर्मांतरण कतई नहीं है, अपितु यह तो 'धर्मोन्मूलन' है; क्योंकि बहुसंख्यक समाज धर्मधारी है और क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है, तो इस्लाम भी एक मजहब है। इन दोनों में से 'धर्म' कतई नहीं है, तो जाहिर है कि धर्मधारी लोगों को रिलीजन या मजहब में तब्दील कर देना उनके धर्म का उन्मूलन ही है 'अंतरण' तो कतई नहीं; यह धर्मांतरण तो तब कहलाता, जब एक धर्म से दूसरे धर्म में अन्तरण होता, अर्थात्, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम भी कोई धर्म होता।

बहरहाल, धर्मोन्मूलन को धर्मांतरण ही मानते हुए उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने सरकार को जो निर्देश दिया है सो त्वरित क्रियावन्धन के योग्य है। धार्मिक स्वतंत्रता की आड में धर्मधारी प्रजा (बहुसंख्यक हिन्दू समाज) के ईसाईकरण अथवा इस्लामीकरण का छत्र अभियान चला रहे रिलीजियस-मजहबी संस्थाओं को परोक्षतः करारा जवाब देते हुए उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि किसी धार्मिक व्यक्ति को धर्म से विमुख कर उसे रिलीजन या मजहब में तब्दील कर दिया जाए। बकौल न्यायालय, लोभ लालच प्रलोभन दे कर या भयभीत कर भोले-भाले (धार्मिक) लोगों का ईसाईकरण अथवा इस्लामीकरण किया जाना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। सर्वोच्च न्यायालय का तो यह भी मानना है कि इस प्रकार के अभियान से भारत राष्ट्र की एकता-अखण्डता व राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है; अतएव इसे रोका जाना अनिवार्य है। जाहिर है सर्वोच्च न्यायालय की यह चिन्ता व मान्यता भारत के 'राष्ट्रीय युवा'- स्वामी विवेकानन्द और महान स्वतंत्रता सेनानी महर्षि अरविन्द के चिन्तन-उद्बोधन पर आधारित है।

मालूम हो कि स्वामी विवेकानन्द ने कह रखा है कि धर्मांतरण एक प्रकार से राष्ट्रान्तरण है। धर्म से विमुख हुआ व्यक्ति जब 'रिलीजन' व 'मजहब' को अपना लेता है, तब वह प्रकामत से भारत के विरुद्ध हो जाता है; क्योंकि धर्म तो भारत की आत्मा है, जबकि 'रिलीजन' व 'मजहब' अन्धकारी अवधारणा हैं। इसी तरह से महर्षि अरविन्द का



कथन है कि धर्म (सनातन) ही भारत की राष्ट्रियता है और धर्मांतरण से भारतीय राष्ट्रियता क क्षरण अवश्यभावी है। भारत के इतिहास और भूगोल में यह तथ्य सत्य सिद्ध हो चुका है। भारत-विभाजन अर्थात् पाकिस्तान-सूजन और खण्डित भारत के भीतर यत्र-तत्र रिलीजियस-मजहबी जनसंख्या के बढ़ते आकार से उत्पन्न विभाजनकारी पृथक्तावादी अन्दोलन इसके प्रमाण हैं। सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त चिन्ता को इसी परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। इसी कारण से महात्मा गांधी भी धर्मांतरण का मुखर विरोध करते रहे थे एवं चर्च-मिशनरियों की गतिविधियों पर लगातार सवाल उठाते रहते थे और यहां तक कह चुके थे कि स्वतंत्र भारत में धर्मांतरणकारी संस्थाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। 'क्रिश्चियन मिशनर्स- देयर प्लेस इन इण्डिया' नामक पुस्तक के 'टांक विथ मिशनरिज' अध्याय में महात्मा गांधी के हवाले से कहा गया है कि भारत में आम तौर पर ईसाइयत का अर्थ भारतीयों को राष्ट्रियता से रहित बनाना तथा उनका यूरोपीकरण करना है। आगे वे कहते हैं- भारत में ईसाइयत अराष्ट्रीयता एवं यूरोपीकरण का पर्याय हो चुकी है। चर्च-मिशनरियां धर्मांतरण का जो काम करती रही हैं, उन कामों के लिए स्वतंत्र भारत में उन्हें कोई भी स्थान एवं अवसर नहीं दिया जाएगा; क्योंकि वे समस्त भरतवर्ष को नुकसान पहुंचा रही हैं। भारत में ऐसी किसी चीज का होना एक त्रासदी है। सन 1935 में चर्च-मिशन की एक प्रतिनिधि से हुई भेंटवाता में महात्मा साफकहा था- अगर सत्ता मेरे हाथ में हो और मैं कानून बना सकू तो मैं धर्मांतरण का यह सारा धंधा ही बन्द करा दूंगा। (सम्पूर्ण गांधी वांगमय- खण्ड 61) सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त चिन्ता के परिप्रेक्ष्य में गांधीजी की वह घोषणा आज भी प्रासंगिक है।

बावजूद इसके आज देश भर में ऐसी रिलीजियस-मजहबी संस्थाओं का जाल बिछा हुआ है, जो शिक्षा-स्वास्थ्य-सेवा के विविध प्रकल्पों और

सामाजिक न्याय व समता-स्वतंत्रता के विविध आकर्षक सञ्जकों एवं विकास-परियोजनाओं की ओट में देसी-विदेशी धन के सहारे छलपूर्वक धर्मांतरण का धंधा संचालित कर रही हैं। इन संस्थाओं की कारगुजारियों के कारण यहां कभी 'असहिष्णुता' का ग्राफ ऊपर की ओर उठ जाता है, तो कभी 'अल्पसंख्यकों की सुरक्षा' का ग्राफ नीचे की ओर गिरा हुआ बताया जाता है। ये संस्थायें भिन्न-भिन्न प्रकृति और प्रवृत्ति की हैं। कुछ शैक्षणिक-अकादमिक हैं, जो शिक्षण-अध्ययन के नाम पर भारत के विभिन्न मुदों पर तरह-तरह का शोध-अनुसंधान करती रहती हैं; तो कुछ संस्थायें ऐसी हैं, जो इन कार्यों के लिए अनेकानेक संस्थायें खड़ी कर उन्हें साध्य व साधन मुहैया करती-कराती हुई विश्व-स्तर पर उनकी नेटवर्किंग भी करती हैं। 'फ्रीडम हाउस' संयुक्त राज्य अमेरिका की एक ऐसी ही संस्था है, जो भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के नाम पर उन्हें भडकाने के लिए विभिन्न भारतीय-अभारतीय संस्थानों का वित्त-पोषण और नीति-निर्धारण करती है। किन्तु वास्तव में धर्मोन्मूलन (अर्थात् ईसाईकरण या इस्लामीकरण) और भारत-विभाजन ही इसका गुप्त एजेण्डा है, जिसके लिए यह संस्था भारत में कथित अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की इक्की-दुक्की घटनाओं को भी बढ़ा-चढ़ा कर दुनिया भर में प्रचारित करती है। इसी तरह से 'दलित प्रौढम नेटवर्क' (डीएफ़न) नामक एक अमेरिकी संस्था का नियमित पाक्षिक प्रकाशन भी है- 'दलित वायस' जो भारत में पाकिस्तान की तर्ज पर एक पृथक 'दलितस्तान' राज्य की भी वकालत करता रहता है। इन दोनों संस्थाओं को अमेरिकी सरकार का ऐसा वरदहस्त प्राप्त है कि वे अमेरिका-स्थित विभिन्न सरकारी आयोगों के समक्ष भारत से रिलीजियस-मजहबी कार्यकर्ताओं को ले जा- ले जाकर भारत-सरकार के विरुद्ध गवाहियां दिलाता है। ये संस्थायें भारत के बहुसंख्य समाज के विरुद्ध फर्जी अल्पसंख्यक-

उत्पीड़न और उसके निवारणार्थ भारत-विभाजन की वकालत-विषयक शैक्षिक शोध-परियोजनाओं के लिए शिक्षार्थियों व शिक्षाविदों को फेलोशिप व छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इसने कांचा इलाइया नामक उस तथाकथित दक्षिण भारतीय शोधार्थी को उसकी पुस्तक- 'ह्यूई आई एम नॉट ए हिन्दू' के लिए पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप प्रदान किया है, जिसमें अनुसूचित जातियों-जनजातियों-ईसाइयों को सर्वप्र हिन्दुओं के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध के लिए भडकाया गया है।

पीआईएफ़आरएएस (पॉलिसी इंस्टिट्यूट फॉर रिलीजन एण्ड स्टेट) अर्थात् 'पिप्रस' अमेरिका की एक और ऐसी संस्था है, जिसका चेहरा तो समाज और राज्य के मानवतावादी लोकतांत्रिक आधार के अनुकूल नीति-निर्धारण को प्रोत्साहित करने वाला है, किन्तु इसकी खोपड़ी में भारत की वैविधतापूर्ण एकता को खण्डित करने और हिन्दुओं के धर्मांतरण (धर्मोन्मूलन) की योजनायें घुमती रहती हैं। इन धर्मांतरणकारी मिशनरी संस्थाओं का एक वैश्विक गठबन्धन भी है, जिसका नाम- एफ़आईएकेओएनए (द फेडरेशन ऑफ़ इण्डियन अमेरिकन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ़ नार्थ अमेरिका) अर्थात् 'फिआकोना' है। ये दोनों संगठन एक ओर 'इण्टरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम; नामक अमेरिकी कानून के सहारे विश्व-मंच पर भारत को 'मुस्लिम-ईसाई अल्पसंख्यकों का उत्पीड़क देश' के रूप में घेने की साजिशें रचते रहते हैं, तो दूसरी ओर भारत के भीतर नस्लीय भेद एवं सामाजिक घृष्ट पैदा करने के लिए विभिन्न तरह के हथकण्डे अपनाते रहते हैं।

ऐसे में भारत की सम्प्रभुता व अखण्डता की सुरक्षा के लिए धर्मांतरण (धर्मोन्मूलन) पर रोक लगाने के बावत इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इससे भी पहले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को निर्देशित किये जाने के बावजूद सरकार की उदासीनता घोर चिन्ताजनक है। धर्मोन्मूलन (धर्मांतरण) का सदैव ही विरोध करते रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी जब अल्पसंख्यक-कल्याण के नाम पर बहुसंख्यक समाज के योसाईकरण व इस्लामीकरण को बढ़ावा देने वाली पूर्व की कांग्रेसी सरकार द्वारा कायम किए गए अल्पसंख्यक आयोग एवं मुस्लिम वक्फ बोर्ड नामक संस्थाओं और उनकी विभिन्न योजनाओं-यथा- 'मदरसाई शिक्षा', 'वजीप' व व्याज-मुक्त ऋण आदि पर प्रति वर्ष भारी-भरकम बजट का प्रावधान करती रही है, तब इस राष्ट्रीय त्रासदी से भारत राष्ट्र को आखिर कौन उबारेगा ? न्यायालय जब बहुसंख्यक समाज की घटती आबादी पर चिन्ता जताते हुए उसके ईसाईकरण व इस्लामीकरण को रोकने की निर्देश दे रहा है, तब केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह इसके उपाय के तौर पर इन धर्मोन्मूलनकारी (धर्मांतरणकारी) योजनाओं को बन्द करे हुए 'समान नागरिक संहिता' शीघ्र कायम करे और 'मजहबी आबादी नियंत्रण' का सख्त कानून भी कायम करे।

धर्मनिरपेक्ष भारत को यूसीसी से नहीं शरिया से चलाने की जिद क्यों?

संजय सक्सेना

मोदी सरकार द्वारा पहली जुलाई से देश में भारतीय न्याय संहिता लागू किये जाने के बाद अब समान नागरिक संहिता (यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड) का मुद्दा गरमाने लगा है, जिस तरह से मोदी सरकार के मंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यूसीसी के पक्ष में बयानबाजी कर रहा है उससे यूसीसी विरोधियों के भी सूर मुखर होने लगे हैं। सुनी पर्सनल लॉ बोर्ड तो पहले से ही यूसीसी का विरोध कर रहा था, अब शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएसपीएलबी) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समान नागरिक संहिता उन्हें किसी दशा में स्वीकार नहीं है। उनकी कौम देश के कानून से नहीं चलेंगी, बल्कि शरीयत कानून को ही मानेगी। बोर्ड ने धमकी वाले अंदाज में कहा है कि मोदी सरकार यूसीसी बनाने की प्रक्रिया को रोक दे। इसके साथ ही बोर्ड की तरफ से चेतावनी भी दी गई कि यदि मोदी सरकार ने हमारा अनुरोध नहीं माना तो मोहरम के बाद आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे। बोर्ड के यह तैवर तब हैं जबकि भारतीय संविधान से लेकर सुप्रिम कोर्ट तक सभी नागरिकों के लिये समान कानून की बात लम्बे समय से कहता रहा है अलग-अलग मौकों पर देश की तमाम अदालतें सरकार से यूसीसी लागू करने के लिये कानून बनाने की बात भी कह चुकी हैं। वैसे भी एक धर्मनिरपेक्ष देश में सबके लिये एक जैसे कानून में कोई बुराई नजर नहीं आती है।

गौरतलब है कि हाल के वर्षों में समान नागरिक संहिता पर सियासी और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर ही माहौल गर्म रहा है। एक ओर जहाँ देश की बहुसंख्यक आबादी समान नागरिक संहिता को लागू करने की पुरजोर मांग

उठाती रही है, वहीं अल्पसंख्यक वर्ग इसका विरोध करता रहा है। इसी के मद्देनजर इस मुद्दे पर हर चुनाव में खूब राजनीति होती रही है, वहीं चुनाव बाद इस मुद्दे को उठे बस्ते में डाल दिया जाता है, लेकिन लगता है कि अब मोदी सरकार इस पर बड़ा निर्णय लेने का मन बना चुकी है। यूसीसी से सबसे अधिक फायदा महिलाओं को होगा। क्योंकि आज भी किसी भी समाज और कौम में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलना रीगिस्तान में नखिलस्तान से कम नहीं है, लेकिन यूसीसी लागू होने से महिलाओं के सामने कदम-कदम पर आने वाली चुनौतियाँ का ग्राफ थोड़ा कम हो सकता है। अगर चिंता की बात यह है कि एक तरफ जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय नागरिक संहिता को अनुच्छेद 25 का हनन मानते हैं, वहीं इसके झंडाबरदार समान नागरिक संहिता की कमी को अनुच्छेद 14 का अपमान बता रहे हैं।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सांस्कृतिक विविधता से इस हद तक समझौता किया जा सकता है कि समानता के प्रति हमारा आग्रह क्षेत्रीय अखंडता के लिए ही खतरा बन जाए? क्या एक एकीकृत राष्ट्र को 'समानता' की इतनी जरूरत है कि हम विविधता की खूबसूरती को परवाह ही न करें? इसका जवाब हां में है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि देश का संविधान देशवासियों को कुल मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें भाषा और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का अधिकार, (इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ भिन्नता पूर्ण संबंध सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के अधीन दिए जाते हैं)। बोलने, खाने पीने और अपने विचार व्यक्त करने की हमें आजादी है, लेकिन इसी आजादी का जब

लोग गलत फयदा उठाने लगते हैं तो देश को संप्रभुता पर खतरा मंडराने लगता है। इस समय जनता को अधिकार के साथ उनकी जिम्मेदारी से भी अवगत कराया जाता है। समान नागरिक संहिता इसी क्रम की एक कड़ी मात्र है। सवाल उठता है कि अगर हम सदियों से अनेकता में एकता का नारा लगाते आ रहे हैं तो, कानून में भी एकस्पता से आपत्त क्यों? क्या एक संविधान वाले इस देश में लोगों के निजी मामलों में भी एक कानून नहीं होना चाहिए? अगर अब तक समान नागरिक संहिता को लागू करने की कोशिश संजीदगी से नहीं हुई है तो, इसके पीछे अल्पसंख्यक वोट बैंक की सियासत तो नहीं है? बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है। राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि 'राज्य, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा'।

समान नागरिक संहिता में किसी के रीति-रिवाज पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन शादी, तलाक तथा जमीन-जायदाद के बँटवारे आदि में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होता है। अभी देश में जो स्थिति है उसमें सभी धर्मों के लिए अलग-अलग नियम हैं। संपत्ति, विवाह और तलाक के नियम हिंदुओं, मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए अलग-अलग हैं। इस समय देश में कई धर्म के लोग विवाह, संपत्ति और गोद लेने आदि में अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना-अपना पर्सनल लॉ है जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं।

गौरतलब हो संविधान निर्माण के बाद से ही समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग उठती रही है। लेकिन, जितनी बार मांग उठी है उतनी ही बार इसका विचार भी हुआ है। समान

नागरिक संहिता के हिमायती यह मानते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव करने की मनाही और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और निजता के संरक्षण का अधिकार लोगों को दिया गया है। लेकिन, महिलाओं के मामले में इन अधिकारों का लगातार हनन होता रहा है। बात चाहे तीन तलाक की हो, मंदिर में प्रवेश को लेकर हो, शादी-विवाह की हो या महिलाओं की आजादी को लेकर हो, कई मामलों में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। इससे न केवल लैंगिक समानता को खतरा है बल्कि, सामाजिक समानता भी सवालियों के घेरे में है। जाहिर है, ये अनुसूचित हैं। लिहाजा, समान नागरिक संहिता के झंडाबरदार इसे संविधान का उल्लंघन बता रहे हैं। दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुस्लिम समाज समान नागरिक संहिता का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा जाता है कि संविधान ने देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। इसलिए, सभी पर समान कानून थोपना संविधान के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। मुस्लिमों के मुताबिक उनके निजी कानून उनकी धार्मिक आस्था पर आधारित हैं इसलिए समान नागरिक संहिता लागू कर उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए। दरअसल, समान नागरिक संहिता को लागू करने की पूरजोर मांग उठने के बाद भी इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका है। कई मौके ऐसे आए जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी समान नागरिक संहिता लागू न करने पर नाखुशी जताई है। 1985 में शाह बानो केस और 1995 में सरला मुदागल मामले में सुप्रिम

कोर्ट द्वारा समान नागरिक संहिता पर टिप्पणी से भी इस मुद्दे ने जोर पकड़ा था, जबकि पिछले वर्ष ही तीन तलाक पर सुप्रिम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद भी इस मुद्दे को हवा मिली। लेकिन, सवाल है कि इस मसले पर अब तक कोई ठोस पहल क्यों नहीं हो सकी है? दरअसल, भारत का एक बहुल संस्कृति वाला देश होना इस रास्ते में बड़ी चुनौती है। हिंदू धर्म में विवाह को जहाँ एक संस्कार माना जाता है, वहीं इस्लाम में इसे एक अनुबंध माना जाता है। ईसाइयों और पारसियों के रीति- रिवाज भी अलग-अलग हैं। मौजूदा वक में गोवा और उत्तराखंड दो ऐसे राज्य हैं जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। जाहिर है, इसके लिए काफी प्रयास किए गए होंगे। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि दूसरे राज्यों में भी अगर कोशिश की जाती है तो, इसे लागू करना मुमकिन हो सकता है। दूसरी ओर वोटबैंक की राजनीति भी इस मुद्दे पर संजीदगी से पहल न होने की एक बड़ी वजह है। एक दल जहाँ समान नागरिक संहिता को अपना एजेंडा बताता रहा है, वहीं दूसरी पार्टियाँ इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ सरकार को राजनीति बताती रही हैं। जाहिर है, एक दल को अगर वोट बैंक के खिसक जाने का डर है तो, दूसरे को वोट बैंक में संघ लगाने की फिक्र है। दरअसल, सियासी दलों का यह डर पुराना है। बता दें यूसीसी की तरह ही 1948 में जब हिन्दू कोड बिल संविधान सभा में लाया गया, तब देश भर में इस संहिता का जबरदस्त विरोध हुआ था। बिल को हिन्दू संस्कृति तथा धर्म पर हमला करार दिया गया था। सरकार इस कदर दबाव में आ गई कि तत्कालीन कानून नवीं भीमराव अंबेडकर को पद से इस्तीफा देना पड़ा। यही कारण है कि कोई भी राजनीतिक दल समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर जोखिम नहीं लेना चाहता। हमें समझना होगा कि जब हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होगा।

संक्षिप्त समाचार

उड़ान भरते ही निकल गया बोइंग विमान का पहिया, अटक गई सैकड़ों यात्रियों की जान

लॉस एंजलिस, एजेंसी। बोइंग विमान ने एक बार फिर सैकड़ों यात्रियों की जान को खतरे में डाल दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में यूनाइटेड एयरलाइंस के बोइंग जेट विमान का पहिया सोमवार को उड़ान भरते समय निकल गया। हालांकि, बाद में विमान को डेनवर में सुरक्षित उतार लिया गया। विमानकंपनी ने यह जानकारी दी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बयान के मुताबिक, लॉस एंजलिस में विमान का पहिया बराबर कर लिया गया था। घटना के पीछे की वजहों की जांच कर रहे हैं। घटना के समय बोइंग 757-200 विमान में 174 यात्री और चालक दल के सात सदस्य सवार थे। इससे पहले, सात मार्च को सैन फ्रांसिस्को से उड़ान भरने वाले यूनाइटेड एयरलाइन के बोइंग बी777-200 जेट विमान का पहिया बीच हवा में टूटकर गिर गया था। घटना के कारण विमान हवाई अड्डे के पार्किंग क्षेत्र में एक कार के ऊपर जा गिरा था। हालांकि, इससे कोई घायल नहीं हुआ था।

ईरान की नौसेना का विध्वंसक जहाज डूबा, कई लोग घायल

तेहरान, एजेंसी। ईरानी नौसेना का एक जहाज होर्मुज की खाड़ी के पास एक बंदरगाह में डूब गया। मुरुमत के दौरान विध्वंसक पोत 'सहद के टैंकों में पानी घुस गया जिसके कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह डूब गया। एजेंसी ने बताया कि जिस जगह जहाज डूबा है, वहां पानी की गहराई कम है अतः संभावना है कि जहाज संतुलन हासिल कर ले। हृदय में कई लोग घायल हो गए हैं। यह घटना होर्मुज जलडमरूमध्य के पास बंदर अम्बास के दक्षिणी बंदरगाह में हुई, जब जहाज के टैंकों में पानी घुस गया। सरकारी मीडिया ने यह भी बताया कि कई लोगों को मामूली चोटें आईं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इसमें यह भी बताया गया कि इस घटना में कुछ लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन घायलों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। 'सहद जहाज का नाम उत्तरी ईरान के एक पर्वत के नाम पर रखा गया है और इस जहाज को बनाने में छह वर्ष लगे। इसे दिसंबर 2018 में फारस की खाड़ी में भेजा किया गया। कुल 1,300 टन वजन की यह जहाज जमीन से जमीन और जमीन से आसमान में चार करने वाली मिसाइलों, विमान भेदी तोप से सुसज्जित है और इसमें अत्याधुनिक रखर बचने की क्षमता है।

ब्रिटिश कोलंबिया में 5 पंजाबी छात्रों को मिली 1.95 करोड़ की स्कॉलरशिप

ओटावा, एजेंसी। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में विभिन्न स्कूलों से स्नातक करने वाली 5 पंजाबी छात्रों को शैक्षिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले संस्थानों द्वारा 3 लाख 22 हजार डॉलर यानी लगभग 1 करोड़ 95 लाख रुपए का वजीफा दिया गया है। खालसा सेकेंडरी स्कूल की प्रतिभाशाली छात्रा हरनूर कौर धालीवाल को यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया प्रेसिडेंशियल स्कॉलर्स अवार्ड के तहत 80,000, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी से 40,000, बीसी एक्सप्लोरर्स से 5,000, सिख हेरिटेज से 1,500 और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से 1,250 डॉलर मिले हैं, जिया गिल, गेविन रॉय और तमन्ना कौर गिल को 1 लाख 80 हजार डॉलर की स्कॉलरशिप दी गई है। तमन्ना कौर गिल को यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया प्रेसिडेंशियल स्कॉलर्स अवार्ड के तहत 15 हजार डॉलर की स्कॉलरशिप भी मिली है।

रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से कीव पर किया अटक, हमले में 20 लोगों की मौत, 50 घायल

कीव, एजेंसी। यूक्रेन की वायु सेना ने कहा कि रूसी सेना ने सोमवार को यूक्रेनी टैंकों पर कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागीं, राजधानी कीव में विस्फोटों को महसूस किया गया और सुना गया। शहर के विभिन्न हिस्सों से धुआं उठता देखा गया। यूक्रेन के आंतरिक मंत्रालय ने इस हमले की जानकारी देते हुए बताया कि इस रूसी हमले में 20 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 50 लोग घायल हैं। वायुसेना ने बताया कि दिन के उजाले में किए गए इस हमले में किंगल हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया।

बोइंग ने फॉड के आरोप कबूले 2 क्रेश, 346 लोगों की मौत के बावजूद सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा

4 हजार करोड़ रुपए जुर्माना लगा

वाशिंगटन, एजेंसी।

अमेरिका की विमान कंपनी बोइंग को फॉड के आरोप में दोषी पाया गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी न्याय विभाग ने पाया कि बोइंग ने 2018-2019 में हुए 2 क्रेश के बाद कंपनी को सुधारने के लिए की गई डील का उल्लंघन किया है। बोइंग ने इसे लेकर 243.6 मिलियन डॉलर यानी 4 हजार करोड़ रुपए का जुर्माना भरने पर सहमत जताई है। इसके अलावा कंपनी अगले 3 साल तक विमानों की सेफ्टी पर 4 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी।

दरअसल, 2018 और 2019 में पांच महीने के अंदर इंडोनेशिया और इथोपिया में बोइंग कंपनी के 737 मैक्स विमान क्रेश हो गए थे। इन हदसों में 346 लोगों की जानें गई थीं। इसके बाद कई तरह की जांच का सिलसिला शुरू हुआ। जांच में विमान में कई तरह की गड़बड़ी सामने आईं।

कंपनी को मुत्तकों के परिजनों से मुलाकात करने को भी कहा गया है। बोइंग तीन साल के लिए कोर्ट की निगरानी में रहेगी। कोर्ट के मेंबर्स फ्लाइंट में सुरक्षा को जांचेंगे और इसकी एक रिपोर्ट सालाना सरकार को देंगे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा। सुबह 6 बजकर 21 मिनट पर बोइंग-737 के मैक्स 8 विमान ने इंडोनेशिया के सोएकरानो-हट्टा हवाई अड्डे से उड़ान भरी। इसे 7 बजकर 20 मिनट पर इंडोनेशिया के ही एक छोटे से शहर पंगकाल पिनांग जाना था। पर ऐसा नहीं हुआ। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही विमान के करू ने एयर ट्रेफिक कंट्रोल से संपर्क



बच्चों का अस्पताल तबाह, 31 की मौत

मास्को, एजेंसी। रूस ने बीते चार महीने में यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला किया है। रूस के ताबड़तोड़ मिसाइलें अटक से यूक्रेन में 31 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। रूस ने बच्चों के एक अस्पताल पर भी हमला किया है जिसकी इमारत को काफी नुकसान पहुंचा है। अलग-अलग जगहों पर किए गए हमले में कम से कम 154 लोग घायल भी हुए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक बयान में कहा कि रूसी बमबारी ने पांच यूक्रेनी शहरों को विभिन्न प्रकार की 40 से अधिक मिसाइलों से निशाना बनाया, जिससे रिहाइशी इमारतें और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे नष्ट हो गए।

क्रोवी रीह में नगर प्रशासन के प्रमुख ओलेक्सान्द्र विल्कुल ने कहा कि यह एक बड़े पैमाने पर किया गया मिसाइल हमला था, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गयी और 47 अन्य लोग घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने यूक्रेन के मध्य दिनप्रोपेटोव्स्क क्षेत्र में भी विस्फोट की सूचना दी है। अधिकारियों ने बताया कि राहतकर्मों कीव के ओखमाटडिट बाल अस्पताल की आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त इमारत के मलबे से लोगों की तलाश में जुटे हैं। मेयर विटाली क्लिट्स्को ने बताया कि कम से कम 16 लोग घायल हुए हैं, जिनमें सात बच्चे शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि बच्चों के अस्पताल की दो मंजिला इमारत आंशिक रूप से नष्ट हो गई। अस्पताल की मुख्य 10 मंजिला इमारत की छिड़कियां और दरवाजे उखड़ गए और दीवारें काली पड़ गयीं।



जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर कहा, %यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी को यह देखना चाहिए कि रूस क्या कर रहा है।% यह हमला दुनिया अब इस बारे में चुप न रहे और

फ्रांस के संसदीय चुनाव में किसी को बहुमत नहीं; त्रिशंकु संसद के आसार, बढ़ेगा राजनीतिक संकट



पेरिस, एजेंसी। फ्रांस में हुए संसदीय चुनाव में वामपंथी गठबंधन ने रिवार को धुर-दक्षिणपंथी दलों को शिकस्त देते हुए सबसे ज्यादा सीटें जीतीं। हालांकि, वह बहुमत हासिल करने में नाकाम रहा, जिससे देश में राजनीतिक संकट गहराने के साथ ही त्रिशंकु संसद की आशंका बढ़ गई है। फ्रांस में राजनीतिक उथल-पुथल से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है और यूक्रेन में युद्ध, वैश्विक कूटनीति तथा यूरोप की आर्थिक स्थिरता पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। फ्रांस की संसद का कार्यकाल 2027 में खत्म होना था, लेकिन यूरोपीय संघ में नौ जून को बड़ी हार मिलने के बाद राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने समय से पहले संसद

भंग कर बड़ा दांव खेला था। उन्होंने कहा था कि एक बार फिर मतदाताओं के बीच जाने से स्थिति 'स्पष्ट' होगी। हालांकि, उनका यह दांव लाभग ह्र पड़ाव पर उल्टा पड़ता दिखा है। सोमवार को जारी आधिकारिक नतीजों के मुताबिक, संसदीय चुनाव में तीनों प्रमुख गठबंधन में से कोई भी 577 सदस्यीय नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए जरूरी 289 सीटों का जादुई आंकड़ा नहीं हासिल कर सका। नतीजों के अनुसार, वामपंथी तथा यूरोप की आर्थिक स्थिरता पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। फ्रांस की संसद का कार्यकाल 2027 में खत्म होना था, लेकिन यूरोपीय संघ में नौ जून को बड़ी हार मिलने के बाद राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने समय से पहले संसद

धुर-दक्षिणपंथी पार्टी 'नेशनल रैली और उसके सहयोगी दलों को 140 से अधिक सीटों पर जीत के साथ तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। जब पार्टी को 89 सीटें हासिल हुई थीं। आधुनिक फ्रांस को अभी तक त्रिशंकु संसद का सामना नहीं करना पड़ा है। प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल ने कहा, 'हमारा देश एक अभूतपूर्व राजनीतिक स्थिति का सामना कर रहा है। वह अगले कुछ हफ्तों में दुनिया का स्वागत करने की तैयारियों में जुटा है। अटल सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। हालांकि, उन्होंने कहा है कि पेरिस ओलंपिक के मद्देनजर वह 'जब तक जरूरत है, तब तक पद पर बने रहने के लिए तैयार है।

सिंगापुर में नाबालिग से रेप के दोषी भारतीय मूल के शख्स को 13 साल जेल



सिंगापुर, एजेंसी। सिंगापुर की एक अदालत ने भारतीय मूल के एक शख्स को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए सोमवार को 13 साल चार सप्ताह की जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी को नौ कोड़े को पड़ेगे। 42 वर्षीय राज कुमार बाला को पीड़िता के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ के अलग-अलग आरोप लगे हैं। इसके अलावा उसे 'विल्डन एंड यंग पर्सन एक्ट' के तहत दोषियों को शरण देने के मामले में भी दोषी ठहराया गया है। आरोपी बाला भारतीय मूल का है, जिसके पास अब सिंगापुर की नागरिकता है। वह सिंगापुर में एक बार का चलाता है। समाचार चैनल 'न्यूज एशिया' की खबर के मुताबिक अदालत को बताया गया कि पीड़िता फरवरी 2020 में सिंगापुर बालिका गृह से भाग गई थी और उस समय उसकी उम्र 17 वर्ष थी। उसी की तरह भागी हुई एक दूसरी लड़की को उसे डनलप स्ट्रीट पर स्थित बाला के बार 'डॉन बार और बिस्ट्रो' में नौकरी के बारे में पता चला।

शाही महल को ही किराये पर देगा सऊदी अरब, तेल के संकट से उबरने की नई कोशिश

रियाद, एजेंसी।

कच्चे तेल की सप्लाई से अर्थव्यवस्था को चलाने वाले सऊदी अरब के आगे संकट खड़ा है। दुनिया भर में जिस तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों का विकल्प बढ़ रहा है, उससे कच्चे तेल की डिमांड में कमी आ सकती है। ऐसी स्थिति सऊदी अरब, कुवैत, कतर जैसे देशों के लिए चिंता की बात है। सऊदी अरब ने तो इसकी काट भी खोजना शुरू कर दिया है और उस पर तेजी से काम भी कर रहा है। इसके तहत उसने खेल के आयोजनों को बढ़ावा दिया है तो वहीं मनोरंजन के कार्यक्रम भी करा रहा है। यही नहीं पर्यटन को भी सऊदी अरब बढ़ावा देने पर काम कर रहा है।



अब पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से सऊदी अरब अपने शासक रहे सऊद बिन अब्दुलअजीज के महल को भी किराये पर देगा। इस महल में पर्यटक रातें गुजार सकेंगे। 3 लाख 65 हजार वर्ग फुट का यह विशाल महल आधुनिक सऊदी अरब के दूसरे शासक सऊद बिन अब्दुलअजीज का घर हुआ करता था। रेड पैलेस के नाम से विख्यात इस महल को 1940 में तत्कालीन क्राउन प्रिंस के लिए तैयार किया गया था। अब इसे अल्ट्रा लजरजी होटल के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इस महल में ठहर कर लोगों को सऊदी अरब की शाही ज़िंदगी

के अनुभव मिल सकेंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार महल को नया रूप बूटीक रूप दे रहा है, जो एक बिल्डर कंपनी है। दशकों तक यह महल शासक का आवास होता था और फिर सरकार का इसे मुख्यालय बना दिया गया था। अब यह एक होटल के तौर पर विकसित होगा। इसके कुल 70 कमरों में पर्यटक रुकेंगे। इससे लोगों को न सिर्फ ठहरने का मौका मिलेगा बल्कि सऊदी अरब की शाही ज़िंदगी के भी दीवार हो सकेंगे। इसके अलावा इस होटल में सऊदी अरब के शाही परिवार के पसंदीदा व्यंजन

अमेरिका में तीन दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन की पूर्व संस्था पर हुआ है। सम्मेलन में इस बात पर विचार किया जाएगा कि किस प्रकार यूक्रेन को गठबंधन के अटूट समर्थन का भरोसा दिलाया जाए तथा यूक्रेनवासियों को यह आशा प्रदान की जाए कि उनका देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के सबसे बड़े संघर्ष से उबर सकता है। यह पिछले कई महीनों में कीव पर सबसे बड़ी बमबारी थी। यूक्रेनी वायु सेना ने कहा कि दिन के उजाले में किए गए हमलों में किंगल हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल थे, जो सबसे उन्नत रूसी हथियारों में से एक है। यह ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक रफ्तार से उड़ता है, जिससे इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। विस्फोटों से शहर की इमारतें हिल गईं।

खालिस्तानी संगठन एसएफजे के खिलाफ मिले नए सबूत, सरकार और 5 साल के लिए बढ़ाएगी बैन

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में बैठे खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ सरकार, केंद्र के तहत पांच साल का बैन आगे बढ़ाने की तैयारी में है। नेशनल इन्वैस्टिगेटिव एजेंसी ने पन्नू और उसके संगठन एसएफजे के खिलाफ जांच जारी रखी थी, जिसमें कुछ नए सबूत मिले हैं। इसके बाद सरकार ने इस पर एक बार फिर से बैन लगाने की तैयारी कर ली है। इससे पहले सितंबर 2019 में पहला बैन लगा था। एनआईए ने पन्नू और एसएफजे के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा केसों में छानबीन की जिसके चलते पंजाब और चंडीगढ़ स्थित पन्नू की संपत्ति को भी सील कर दिया गया था।

एसएफजे का 5 साल का बैन खत्म होने वाला है, ऐसे में सरकार नए सबूत मिलने के बाद बैन खत्म होने के पहले ही नया बैन लगाने की तैयारी में है। एजेंसी के अनुसार, पन्नू पंजाब और पूरे भारत में युवाओं को इंटरनेट के जरिए भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और आतंकी घटनाओं में शामिल होने के लिए उकसाता है। वहीं पन्नू का संगठन भी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते युवाओं को भड़काने की कोशिश करता है। एनआईए की जांच के अनुसार पन्नू ही एसएफजे का कर्ताधर है। वह पिछले कई सालों से लगातार पंजाब और बाकी क्षेत्रों के गैंगस्टर और युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए खालिस्तान की आजादी के लिए



लड़ाई लड़ने के लिए उकसाकर भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देता है। पन्नू लगातार भारतीय डिप्लोमैट और सरकार को धमकियां देने के कारण खबरों में बना रहता है। एसएफजे अप्रैल 2022 में हुए मॉडल जेल टिफिन बम मामले में भी शामिल था, इस साक्षि को जर्मनी के निवासी मुल्तानी, जो कि इसी संगठन का सदस्य था, के द्वारा अंजाम दिया गया था। एजेंसी के मुताबिक मुल्तानी लगातार पन्नू के संपर्क में था। वह लगातार पाकिस्तान और भारत में बैठे खालिस्तानी सपोर्टरों के साथ मिलकर युवाओं को आतंकी घटनाओं में शामिल होने, हिंसा को बढ़ाने और पंजाब में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर सक्रिय था।

'आलोचना के बावजूद मैं दृढ़ता से खड़ा हूँ', बाइडन ने कहा- आखिरी तक चुनावी जंग लड़ूंगा

वाशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि तमाम विरोध के बावजूद वह नवंबर में चुनाव खत्म होने तक टिके रहेंगे। वह अपनी मानसिक फिटनेस के बारे में बढ़ती चिंताओं के बावजूद चुनावी यात्रा को जारी रखेंगे। बाइडन ने अपने पत्र में कहा कि अगर मुझे लगता कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को नहीं हरा सकता हूँ तो मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ता। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि मीडिया और अन्य जगहों पर तमाम अटकलों के बावजूद, मैं इस दौड़ में बने रहने, इस दौड़ को अंत तक चलाने और डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हूँ। इसके अलावा बाइडन ने यह भी कहा, हमारे पास डेमोक्रेटिक सम्मेलन के लिए 42 दिन और आम चुनाव के लिए 119 दिन बाकी हैं। ये सभी बातें बाइडन ने अपने पुनर्निर्वाचन अभियान द्वारा वितरित पत्र में कही हैं। बाइडन ने अपने पत्र में आगामी चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर बल देते हुए अपनी पार्टी के बीच एकता का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में चार महीने का ही समय बाकी है, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी अपने उम्मीदवार को लेकर दुविधा में है।

संक्षिप्त समाचार

प्रबंधक पद के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु 25 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

महासमुंद (समय दर्शन)। जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित महासमुंद के प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति बोकामुड़ा, परसदा, बल्दीडीह एवं देवरी में प्रबंधक पद के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से 25 जुलाई 2024 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रबंधक संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित ने बताया कि आवेदन का प्रारूप एवं चयन प्रक्रिया तथा वेतन भत्ते व अन्य संबंधित जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर के वेबसाइट www.cgmfpfed.org एवं जिले के वेबसाइट www.mahasamund.gov.in तथा संबंधित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित महासमुंद के नाम से जिला युनिवर्सिटी कार्यालय महासमुंद में रजिस्टर एड/सीडी पोस्ट के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन मान्य नहीं होगा। प्रबंधक पद के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, संस्था क्षेत्र का निवासी एवं 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 500 गड्डी तैदुपता संग्रहण का कार्य किया हो। साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का एक वर्षीय डिप्लोमा या डिप्लोमा आवश्यक है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने किया पर्यवेक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी

जांजगीर-चांपा (समय दर्शन)। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती अनिता अग्रवाल द्वारा एकीकृत बाल विकास परियोजना जांजगीर अन्तर्गत सिवनी सेक्टर में आंगनबाड़ी हाथीटिकरा केन्द्र क्रमांक 01 का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी हाथीटिकरा का केन्द्र क्रमांक 01 में कुल 20 बच्चों दर्ज हैं। निरीक्षण के दौरान उपस्थित पंजी में 12 बच्चों की उपस्थिति दर्ज पाई गई। जिसमें से केन्द्र में कुल 3 बच्चों ही उपस्थित पाये गए। आंगनबाड़ी हाथीटिकरा के केन्द्र क्रमांक 01 में साफ-सफाई का अभाव, अनौचारिक शिक्षा का अभाव पाया गया एवं रेडी टू इट उपलब्ध नहीं है, गरम भोजन का सामग्री माह भर के लिये उपलब्ध नहीं पाया गया तथा पर्यवेक्षक द्वारा आं.बा. का निरीक्षण 18 मई 2024 के पश्चात् आज दिनांक तक किया जाना नहीं पाया गया। उक्त संबंध में संबंधित पर्यवेक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिया गया तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का दो दिवस का मानदेय काटने हेतु परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना जांजगीर को आदेशित किया गया।

अब 1200 से ज्यादा शहरों में हाई स्पीड वाई-फाई उपलब्ध: गोपाल विट्टल



आजकल, वाई-फाई हर किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। ये हमारे घरों में काम करते, सीखने और मनोरंजन करने के तरीके को बदल रहा है। अब घर पर स्मार्ट डिवाइस, पढ़ाई और ऑफिस के काम के लिए हमें हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत है। पहले एयरटेल वाई-फाई सिर्फ कुछ ही जगहों पर मिल पाता था, लेकिन इस परेशानी को दूर करने के लिए एयरटेल ने लगातार प्रयास किया है और अब 1200 से ज्यादा शहरों में हाई स्पीड वाई-फाई उपलब्ध करा दिया है। इसका मतलब है कि अब आप भी हाई-स्पीड इंटरनेट का आनंद ले सकते हैं।

इसी उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए, हम आपके लिए और भी फायदे लेकर आए हैं। 1. अब आपके वाई-फाई प्लान में ही टीवी शो, फिल्में और वेब सीरीज का सबसे बड़ा कलेक्शन शामिल है। एयरटेल वाई-फाई के साथ आपको 22 से ज्यादा हज़ार प्लेटफॉर्म और 350 से ज्यादा टीवी चैनल मिलेंगे। 2. इसके अलावा, आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, अब जब भी आप कोई नई एयरटेल सर्विस लेंगे - मोबाइल, कंटेनर या वाई-फाई, तो हम आपको आपके बेसिक प्लान पर अतिरिक्त फायदे देंगे। अगर आप नया एयरटेल वाई-फाई कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो बस यहां <https://www.airtel.in/blog/wifi/unlimited-entertainment-with-airtel-wifi/> हमेशा की तरह, आपके सुझावों और फीडबैक का स्वागत है ताकि हम अपनी सर्विस को आपकी जरूरतों के और भी ज्यादा अनुकूल बना सकें।

ग्राम लेंधरा के वैष्णव परिवार में सम्पन्न हुआ 4 बटुकों का उपनयन संस्कार...

सांगढ़ (समय दर्शन)। बरमकेला अंचल के ग्राम लेंधरा के भागीरथी दास गुरुजी परिवार में उपनयन संस्कार कार्यक्रम वैदिक विधी से सम्पन्न हुआ। हिंदू धर्मों के 16 संस्कारों में से 10वां संस्कार है उपनयन संस्कार। इसे यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। उप यानी पानस और नयन यानी ले जाना अर्थात् गुरु के पास ले जाने का अर्थ है उपनयन संस्कार। प्राचीन काल में इसकी बहुत ज्यादा मान्यता थी। वर्तमान की बात करें तो आज भी यह परंपरा कायम है। लोग आज भी जनेऊ संस्कार करते हैं। जनेऊ में तीन सूत्र होते हैं। ये तीन सूत्र तीन देवता के प्रतीक हैं यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यह संस्कार करने से शिशु को बल, ऊर्जा और तेज की प्राप्ति होती है। यही नहीं, शिशु में आध्यात्मिक भाव जागृत होता है। शास्त्रों तथा पुराणों में तो यहां तक कहा गया है कि इस संस्कार



के द्वारा ब्राह्मण-क्षत्रिय और वैश्य का द्वितीय जन्म होता है। विधिवत् यज्ञोपवीत धारण करना इस संस्कार का मुख्य अङ्ग है।

4 बटुकों का हुआ सामूहिक यज्ञोपवीत -- बरमकेला अंचल के सम्मानित भागीरथी दास वैष्णव परिवार में एक साथ 04 बालकों बटुक लीलाधर, बटुक पृथ्वीधर, बटुक नमन, बटुक ईशान्त का एक साथ उपनयन संस्कार ना सिर्फ लेंधरा में अपितु पूरे बरमकेला अंचल में चर्चा का विषय रहा जिसे देखने 03 दिनों तक लोगों की भीड़ उमड़ती रही। अंतिम दिवस में नगर भ्रमण किया गया जिसमें बटुको द्वारा द्वार द्वार जाकर भिक्षावादन किया गया यह परिदृश्य बेहद ही भावुक और हृदयस्पर्शी रहा। उक्त कार्यक्रम में प्रदेश वैष्णव युवा अध्यक्ष विश्वनाथ बैरागी, डमरूधर वैष्णव, अकाश बैरागी समेत सैकड़ों वैष्णव जन उपस्थित रहे।

काँफी विथ कलेक्टर कार्यक्रम का सफल आयोजन

युवोदय कार्यक्रम के वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ कार्यक्रम

दुर्ग (समय दर्शन)। कलेक्टर सुश्री रज्जा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में युनिसेफ (छ.ग.) एवं एग्रीकॉन फंडेशन के संयुक्त प्रयास से काँफी विथ कलेक्टर कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। युवोदय स्वयं सेवा अभियान के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम फ्रीस्ट मिलाट कैफे में आयोजित किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में युवोदय स्वयंसेवकों ने एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना और उन्हें समाज सेवा के लिए प्रोत्साहित करना था। जिले के प्रशासनिक कार्यक्रमों में जन भागीदारी बढ़ाने तथा विभिन्न सामाजिक मुद्दों के प्रति युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने इस अभियान की शुरुआत की गई। जिला

प्रशासन एवं युनिसेफ के संयुक्त पहल से यह अभियान 7 जून 2023 को प्रारंभ हुआ। इस एक वर्ष के दौरान विभिन्न सामाजिक मुद्दों जैसे सामुदायिक-मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, स्वच्छता, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन, पोषण, किशोर-किशोरी संपूर्ण स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, एएनसी चेकअप, आदि में स्वयंसेवकों की सक्रिय भूमिका रही। साथ ही विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन के दौरान मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों तथा महतारी वंदन योजना के आवेदन प्रक्रिया में सेवा के लिए प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत कलेक्टर सुश्री रज्जा प्रकाश चौधरी द्वारा की गई, जिन्होंने सामाजिक मुद्दों के प्रति युवाओं की सराहना की और समाज में उनके योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा,

युवोदय कार्यक्रम ने हमारे युवाओं को समाज सेवा के माध्यम से खुद को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान किया है। इनके अनुभव और योगदान से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। युवोदय स्वयंसेवकों ने अपनी एक वर्ष की यात्रा के अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे इस कार्यक्रम ने उन्हें न केवल समाज की सेवा करने का मौका दिया, बल्कि व्यक्तिगत विकास के अवसर भी प्रदान किए। कुछ अनुभव साझा करते हुए स्वयंसेवकों ने कहा इस कार्यक्रम ने मुझे समाज की जरूरतों को समझने और उनके लिए काम करने का अवसर दिया है। मैंने इस दौरान कई नई कौशल सीखे और अपने आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस की। युवोदय ने मुझे सिखाया कि छोटे-छोटे कदम भी समाज में बड़े बदलाव ला सकते हैं।

राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत विद्यालय पोटिया में विकासखंड स्तरीय समीक्षा बैठक सह न्यूता भोज सम्पन्न

45 संकुल समन्वयक सहित विभाग के शीर्ष आला अधिकारी हुए शामिल

दुर्ग (समय दर्शन)। राज्य शासन से प्राप्त आदेशों निर्देशों के इम्प्लीमेंट करवाने एवम उनके फेड बैक हेतु ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक डीएमसी श्री सुरेंद्र पांडेय की अध्यक्षता में स्वच्छ प्रेरक मिडिल स्कूल पोटिया धमधा में आज सम्पन्न हुई जिसमें धमधा विकासखंड के 45 संकुल शैक्षिक समन्वयक सहित बीईओ कैलाश साहू, एबीईओ संगीता देवांगन, बेनीराम वर्मा, बीआरसी महावीर वर्मा शामिल हुए। साथ ही अतिथियों हेतु एवं विद्यालय के बच्चों के लिए विकासखंड शिक्षाधिकारी और



पोटिया शाला परिवार की तरफसे विकासखंड स्तर के वरिष्ठ न्यूता भोज का भी आयोजन करवाया गया। का मल्टीमीडिया आधारित शिक्षण प्रदान करने हेतु इन्टीग्रेटेड टच स्क्रीन पैनल युक्त स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया गया। इस क्लास के द्वारा बच्चे आडियो विडियो सिस्टम से पढ़ सकेंगे।

विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की शत प्रतिशत उपस्थिति करें सुनिश्चित- कलेक्टर अग्रवाल



बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए कर्तव्यों का निष्पूरक करें निर्वहन

गरियाबंद (समय दर्शन)। कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने आज शासकीय बालक हायर सेकेण्डरी स्कूल में जिले के सभी संकुल समन्वयकों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कलेक्टर श्री अग्रवाल ने बोर्ड परीक्षा में शत प्रतिशत परीक्षा परिणाम हासिल करने एवं उच्च शिक्षा गुणवत्ता के लिए संचालित गौरव गरियाबंद अभियान के स्वरूप एवं उद्देश्यों की चर्चा की। उन्होंने सभी स्कूलों के बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए संकुल समन्वयकों को सक्रियता के साथ अपने संकुल के स्कूलों का निरीक्षण करने एवं अपने कर्तव्यों का निष्पूरक निर्वहन करने के निर्देश दिए। जिससे स्कूलों में पढ़ाई का बेहतर

माहौल बना रहेगा। परिणाम स्वरूप शत प्रतिशत परीक्षा परिणाम हासिल किये जा सकेंगे। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने स्कूलों में बेहतर परिणाम के लिए विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों की भी शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा स्कूलों में शाला भवनों का रख-रखाव, सफाई व्यवस्था, निर्धारित समय पर स्कूलों का संचालन, बच्चों को पाठ्यपुस्तक वितरण का कार्य समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही जर्जर भवनों में कक्षा संचालित नहीं करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संकुल समन्वयकों को ग्रेडिंग भी की जायेगी। बेहतर परीक्षा परिणाम वाले संकुल समन्वयकों को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा चयनित समन्वयकों को पुरस्कृत भी किया जायेगा। साथ ही खराब परीक्षा परिणाम वाले संकुल

समन्वयकों को जाबबदेही तय की जायेगी। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी ए.के.सारस्वत, डीएमसी के.एस.नायक सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्री अग्रवाल ने संकुल समन्वयकों को गौरव गरियाबंद अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि यह अभियान कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के शत प्रतिशत सफलता हासिल करने के लिए विशेष कार्य योजना है। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में और अधिक मेहनत करते हुए सभी स्कूलों में शत प्रतिशत परीक्षा परिणाम हासिल करने के लिए गंभीरतापूर्वक अधिक प्रयास की जाए। बोर्ड परीक्षा में अच्छे रिजल्ट के लिए बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। साथ ही पाठ्यक्रम के हिसाब से शिक्षकों द्वारा बच्चों को निरंतर मार्गदर्शन एवं लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरणा दी जाए। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने इस अभियान के तहत बनाये गये कार्य योजना को एकरूपता के साथ जिले के सभी स्कूलों में क्रियान्वित करने के लिए सभी संकुल समन्वयकों को निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने संकुल समन्वयकों को उनके संकुल के स्कूलों में मौजूद स्मार्ट कक्षाओं को भी व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। जिससे विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लास के माध्यम से भी बेहतर शिक्षा प्रदान किया जा सकेगा।

नवीन कानूनों के संबंध में जन जागरूकता लाने जिले के मीडियाकर्मियों को दी गई जानकारी

आम जनता को नये कानूनों के बारे में जानकारी देने मीडिया से की सहयोग की अपील

गरियाबंद (समय दर्शन)। देश में विगत 1 जुलाई से लागू हुए 3 नए कानूनों-भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के संबंध में जन जागरूकता लाने के लिए जिले के मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई। राज्य शासन के निर्देश पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले के मार्गदर्शन में पुलिस कार्यालय के सहायक अधिकारी आयोजित कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र चन्द्राकर ने नए कानूनों में किए गए मुख्य परिवर्तन एवं विशेषताओं के बारे में मीडियाकर्मियों को प्रारंभिक जानकारी देते हुए कहा कि मीडिया के माध्यम से इन तीन नये कानूनों के बारे में आम लोगों को जानकारी उपलब्ध हो। मीडिया प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि आम जनता को इन कानूनों के बारे में सही जानकारी और समझ प्रदान



करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि कानूनों की जानकारी के अभाव में नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों का पूरा ज्ञान नहीं हो पाता, जिससे कई बार समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मीडिया जन जागरूकता फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से सही और सटीक जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, जिससे कानून व्यवस्था में सुधार होगा और समाज में शांति और सुरक्षा बढ़ेगी। इस अवसर पर सहायक संचालक जनसंपर्क हेमनाथ सिदार, इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायालय के सहायक लोक अभियोजन अधिकारी रामगोपाल दुबे एवं प्रदीप बेलोडिया ने विभिन्न धाराओं के तहत नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए शामिल किए गए धाराओं, न्याय प्रणाली में प्रौद्योगिकी का समावेश, अपराधों एवं दंडों का पुनर्परिभाषित, आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन, पुलिस की जवाबदेही और बीएनएस की सामान्यतः प्रयुक्त धाराओं तथा मोबाइल ऐप एनसीआरबी आधारित कानूनों का संकलन समय और शीघ्र न्याय के लिए जोड़े गए धाराओं, आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन, पुलिस की जवाबदेही और बीएनएस की सामान्यतः प्रयुक्त धाराओं तथा मोबाइल ऐप एनसीआरबी आधारित कानूनों का संकलन समय और शीघ्र न्याय के लिए जोड़े गए धाराओं के बारे में एवं कानूनों में किए गए मुख्य परिवर्तन एवं विशेषताओं को विस्तार से समझाया। श्री त्रिपाठी ने कहा कि कानूनों की जानकारी के अभाव में नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों का पूरा ज्ञान नहीं हो पाता, जिससे कई बार समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया जन जागरूकता फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मीडिया के माध्यम से सही और सटीक जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, जिससे कानून व्यवस्था में सुधार होगा और समाज में शांति और सुरक्षा बढ़ेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मीडिया इस पहल में सहयोग करेगा और नवीन कानूनों की जानकारी और जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

नवीन कानूनों के संबंध में मीडिया को दी जानकारी

आम जनता को इन कानूनों के बारे में सही जानकारी देने मीडिया से की सहयोग की अपील

महासमुंद (समय दर्शन)। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा तिवारी ने आज पुलिस कंट्रोल रूम महासमुंद में देश में विगत 1 जुलाई से लागू हुए 3 नए कानूनों-भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के संबंध में जिले के मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक कर जानकारी दी गई और अधिक से अधिक जन जागरूकता लाने एवं न्यूज के माध्यम से प्रचार प्रसार कर लोगों तक नवीन कानून को जानकारी साझा करने को कहा।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा तिवारी ने नवीन कानून की जानकारी देते हुए बताया कि इन कानूनों का उद्देश्य समाज में सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर उन्होंने आपराधिक न्याय प्रणाली में किए गए नवाचारों और सुधारों की जानकारी दी, जिससे न्याय की प्रक्रिया और भी प्रभावी और समयबद्ध हो सके। इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता कानून का उद्देश्य न्यायिक



प्रक्रियाओं को सरल और त्वरित बनाना है। इसके तहत न्यायालयों के कार्य में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कानून नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए लागू किया गया है। इसके तहत पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं ताकि वे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने अंतिम नवीन कानून के बारे में बताया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्यों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को

सुनिश्चित करना है। इसके तहत साक्ष्यों के संग्रहण, प्रस्तुति, और मूल्यांकन में सुधार किए गए हैं। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री अजय शंकर त्रिपाठी, एसडीओपी श्री कृष्णा पटेल, रक्षित निरीक्षक दीप्ति करण्य और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसके पश्चात अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री अजय शंकर त्रिपाठी ने कार्यक्रम में नवीन कानून के संबंध में विभिन्न धाराओं के तहत नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए शामिल किए गए धाराओं, न्याय प्रणाली में प्रौद्योगिकी का समावेश,

अपराधों एवं दंडों का पुनर्परिभाषित, आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन, पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता, आईपीसी और बीएनएस की सामान्यतः प्रयुक्त धाराओं तथा मोबाइल ऐप एनसीआरबी आधारित कानूनों का संकलन समय और शीघ्र न्याय के लिए जोड़े गए धाराओं के बारे में एवं कानूनों में किए गए मुख्य परिवर्तन एवं विशेषताओं को विस्तार से समझाया। श्री त्रिपाठी ने कहा कि कानूनों की जानकारी के अभाव में नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों का पूरा ज्ञान नहीं हो पाता, जिससे कई बार समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया जन जागरूकता फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मीडिया के माध्यम से सही और सटीक जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, जिससे कानून व्यवस्था में सुधार होगा और समाज में शांति और सुरक्षा बढ़ेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मीडिया इस पहल में सहयोग करेगा और नवीन कानूनों की जानकारी और जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

संक्षिप्त-खबर

पटवारी से परेशान ग्रामीणों ने एसडीएम को सौपा ज्ञापन, पटवारी को हटाने की रखी, जन समस्या निवारण शिविर में पहुंचे ग्रामीण



पाटन (समय दर्शन)। ग्राम दरबार मोखली में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में आज सरपंच राकेश आडील के नेतृत्व में ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे थे। ग्रामीणों ने एसडीएम पाटन को ज्ञापन सौंपा। जिसमें पटवारी को हटाने की मांग की। सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार ग्रामीणों ने बताया कि पटवारी हल्का नंबर 31 के पटवारी नवीन मिश्रा से किसान काफी परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पटवारी कार्यालय में मौजूद नहीं रहते। वहीं छोटे-छोटे काम के लिए कई बार पटवारी कार्यालय का चक्र लगाना पड़ता है। इसके अलावा छात्र-छात्राओं, पालकों को जाति आय एवं निवासी प्रमाण पत्र के लिए भी भटकना पड़ता है। आज ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर पटवारी को हटाने की मांग की है। जिस पर एसडीएम ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया की उचित कार्रवाई की जाएगी।

फुलझर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भगत देवरी में प्रवेश उत्सव सम्पन्न



बसना (समय दर्शन)। फुलझर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भगत देवरी में प्रवेश उत्सव मनाया गया। प्राचार्य तारेन्द्र कुमार साहू के निर्देशन में नवप्रवेशी छात्र-छात्राओं का हर्षोल्लास के साथ तिलक कर मिष्ठान खिलाकर प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस दौरान निधन छात्र-छात्राओं को विद्यालय गणवेश कापी पुस्तक और जूता मौजा भी प्रदान किये गये। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने छात्र-छात्राओं को नियमित विद्यालय आने, जीवन में अनुशासन, राष्ट्र प्रेम, शिक्षा का महत्व आदि विषय पर उद्बोधन दिये। प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शाला विकास समिति के अध्यक्ष अशोक कानूनगो, सदस्य दुर्गा शंकर जोशी, रोहित कुमार नायक, निशामनी बड़ाई, किरण पटेल, जयलाल बारीक, संदीप अग्रवाल, काशीराम पटेल, राकेश पटेल, चंद्रप्रकाश प्रधान, त्रिनाथ साव, गणेश राम साहू, सरपंच ललित सिदार तथा विद्यालय के सभी शिक्षक आनंद साहू, अरुण किशोर दास, हेमराज प्रधान, वीरेंद्र दास, सुदामा साहू, ललित कुमार साहू, बिसिकेशन साव, साहब लाल साव, परात्पर प्रधान, श्रीमती गायत्री प्रधान, चितरंजन यादव, श्रीमती सुनीता मांझी, विद्यालयीन कर्मचारी सुरेंद्र भोई, चंद्रजय प्रधान, अखिलेश बारीक, तुषार यादव उपस्थित रहे।

वार्ड नंबर 4 एवं 5 में संगम ने वितरण किया पौधा



सरायपाली (समय दर्शन)। संगम सेवा समिति द्वारा विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम के कड़ी में सराईपाली वार्ड क्रमांक 4 एवं 5 पटवारी में घर घर जा कर नीम कटहल जामुन गुलमोहर जाम के पौधों का वितरण किया गया एवं वार्ड वासीयों के आग्रह पर तत्काल में उनके आगन या घर के परिसर में मशीन द्वारा गड्ढा कर वृक्षारोपण किया गया, एवं समिति के संस्थापक प्रखर अग्रवाल द्वारा वार्ड वासीयों से आग्रह किया गया कि वे स्वयं इन पौधों की देखभाल करे, उक्त समय समिति के सदस्य तुषार सेन (अधिवक्ता), आशीष सेन, आशुष साहू, रिकु पटेल, संजय कुमार, आलू नाग, तरुण गड्डितिया, प्रखर शर्मा, किशन जायसवाल, विजय नाग, अभिनय शाह, अभय नंद, सोनू पांडे, अमितेश सागर, नवीन यादव, दीपक नायक, सदस्य उपस्थित रहे।

अवैध शराब की बिक्री पर चौकी भंवरपुर महासमुन्द पुलिस की कार्यवाही

■ आरोपी के कब्जे से 16 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार

बसना (समय दर्शन)। पुलिस अधीक्षक महासमुन्द एवं अनुविभागीय अधिकारी सराईपाली के निर्देशन पर सभी थाना चौकी प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में लगातार गस्त पेट्रोलिंग कर मुखबिरो को सजग कर अवैध शराब निर्माण व बिक्री करने वाले एवं मादक पदार्थ परिवहन पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके तारतम्य में दिनांक 10 जुलाई 2024 को मुखबिर के



जरिए सुचना मिली कि ग्राम डोंगरीपाली के आगे कच्ची रोड किनारे कोई व्यक्ति मोंहा पेड के नीचे महुआ शराब की बिक्री कर रहा है। जिस पर चौकी प्रभारी विनोद कश्यप एवं चौकी टीम की सजगता से पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर के निशानदेही पर ग्राम डोंगरीपाली के आगे कच्ची रोड किनारे मोंहा पेड के पास एक व्यक्ति को घेराबन्धी कर को पकड़ा गया। जिससे नाम पता पछुने पर अपना नाम वीरनारायण चौहान, पिता-स्व. धनसाय चौहान, उम्र-36 वर्ष, साकिन-डोंगरीपाली, चौकी-भंवरपुर, थाना- बसना, जिला-महासमुन्द का निवासी होना बताया।

जिनके कब्जे से 04 नग हरा रंग एवं 04 नग सफेद रंग की 02-02 लीटर वाली प्लास्टिक बाटल में 02-02 लीटर भरी हुई भट्टी भट्टी का बना कच्ची महुआ शराब कुल 16 लीटर शराब मिला। आरोपी को शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जो उक्त शराब को बिक्री एवं रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताया। जिस पर 16 लीटर महुआ शराब कीमत 3200 रुपये जप्त कर आरोपी के विरुद्ध थाना बसना में अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों के हक में आवाज उठाई, जिलाधीश के हाथों शासन को सौंपा मांगपत्र

राजनांदगांव (समय दर्शन)। छा प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा के द्वारा आज बुधवार, 10 जुलाई को कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री छा शासन व मुख्य सचिव छा शासन के नाम ज्ञापन जिलाधीश को सौंपा गया।



उकाशय की जानकारी प्रदान करते हुए जिला शाखा के अध्यक्ष व सचिवद्वय अरुण कुमार देवांगन तथा आनंदकुमार श्रीवास्तव ने कहा कि संघ के प्रांतीय निकाय के आह्वान पर प्रमुख संरक्षक पीआर यादव, प्रदेश अध्यक्ष जीआर चंद्रा, महामंत्री विजय लहरे, संभागीय अध्यक्ष संजय शर्मा के मार्गदर्शन व नेतृत्व में केंद्र के समान देय तिथि से 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने, अवकाश नकदीकरण की पात्रता 300 दिन की किए जाने, पिंगुआ समिति की अनुशंसा प्राप्त कर सभी संवर्गों की वेतन विसंगति में सुधार किए जाने, लिपिकों को अनुकंपा

नौकरी में दी गयी शर्तों के पालन के लिए दृष्टता परीक्षा छः माह में आयोजित करने आदेश जारी करने, अनियमित, दैनिक वेतनभोगी और कार्यभारित कर्मचारियों के नियमितकरण हेतु गठित समिति की अनुशंसा प्राप्त कर नियमित करीब 30 कार्यवाही शीघ्र की जाने आदि मांगों व साथ ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में वर्ष 2013 से कार्यरत करीब 30 नियमित प्रशिक्षण अधिकारियों की गत ग्यारह वर्षों से समाप्त नहीं की गयी परिवीक्षा अवधि को दूर किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किए जाने एवं पदोन्नति, सम्मान, आरपीएल विभागीय परीक्षा का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर मध्यह्व भोजनावकाश के मध्य जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। इसके पूर्व कलेक्टर के सामने बड़ी संख्या में कर्मचारी साथी उपस्थित हुए तथा शासन को सौंपी जाने वाली मांगपत्रों की प्रतियों का वाचन किया जाकर अवगत कराया गया तथा मांगों के समर्थन में पूरे उत्साह पूर्वक जोरदार नारेबाजी की गयी।

ज्ञापन सौंपे जाते समय अध्यक्ष अरुण कुमार देवांगन, सचिव आनंदकुमार श्रीवास्तव सहित हरिश भाटिया, सुभाष तायवाड़े, नरेंद्र साहू, प्रसाद पेंढारकर, धीरज रामटेके, एसके शर्मा, कमलेश दीमर, महेश देवांगन, एसके शर्मा, मानसिंह पवार, भीम सिंह मार्को, श्रीमती बसंती साहू, सुश्री नगमा खान, श्रीमती सविता माहेश्वरी, विजय सिन्हा, भूपेंद्र ठाकुर, श्रीमती सीमा यादव, तूफान सिंह, श्रीमती गायत्री ठाकुर, कुलदीप बोरकर, दुशाल कंवर, चित्रकांत वर्मा, मनोज बोपचे, विकास ठाकुर, दीपक बंजारा, सुश्री प्रिया बघेल, सुश्री सायरा, लक्ष्मीनारायण देवांगन, मनीष श्रीवास्तव, विकास श्रीवास्तव, शिव कुमार साहू, आलोक सुकोतेल, श्रीमती संध्या तारम, श्रीमती तुपति पधारे, चंद्रकला रावटे, राजेंद्र जैन, धीरेंद्र रंगारी, निरंजन सिंह महिपाल, श्री भगत, श्रीमती डी. ईश्वरी तथा आईटीआई पेंड्री व सभी कार्यालयों के कर्मचारी साथी उपस्थित थे।

सड़क की हालत जर्जर, गहरे कीचड़ से लोग परेशान, आए दिन होती हैं दुर्घटनाएँ, लोगों में रोष

बसना (समय दर्शन)। बसना विकासखण्ड के पूर्वोत्तर में बसा ग्राम सागरपाली, सरसीवां, सारंगढ, भटगाँव जाने हेतु विकासखंड मुख्यालय बसना व सरायपाली मुख्यालय मार्ग का संगम स्थल पर बसा है। यह मार्ग सरायपाली, बसना, महासमुन्द जिला से सरसीवां बिलाईगढ जैसे दो जिलों को जोड़ती है। इस अति व्यस्त मार्ग का हालत सदैव पीड़ा दायक रहता है। तात्कालीन सरायपाली विधायक किस्मत लाल नंद की सक्रियता से इस मार्ग का कायाकल्प किया गया था। सागरपाली व्यावसायिक जगह है, यहाँ ग्राम पंचायत के पदाधिकारी विभाग और विधायक को इसकी जानकारी दे चुके हैं कह कर पल्ला झाड़ रहे हैं। संवर्धन की योजना के अभाव में शहरी क्षेत्र में सड़क का हालत बनते-बनते उजड़ जाता है। क्यों कि बस्ती का निस्तारी का पानी रोड के उपर बहता है। गौरतलब हो कि, इस रोड के निर्माण में ठेकेदार द्वारा और न ही ग्राम पंचायत द्वारा आज तक रोड के अगल बगल में पानी निकासी हेतु समुचित नाली की व्यवस्था नहीं की गयी है।



जिसके चलते हालत अत्यंत दयनीय हो गई है, जिसे लेकर सागरपाली क्षेत्र के ग्रामीणों में अत्यंत आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा बार-बार प्रशासन व जन प्रतिनिधियों से इसकी शिकायत करने के बाद भी इसकी समस्या का सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ शहरी एरिया में सड़क मुख्य मार्ग पर ही लगभग 200 मीटर तक यह सड़क पूरी तरह से खराब हो गयी है, और जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं। वाहनों के आवाजाही से सड़क धंस कर कीचड़युक्त गड्ढे में तब्दील हो गये हैं। सागरपाली के सोहन लाल पटेल (पूर्व सभापति, जनपद पंचायत बसना), वृंदावन साहू (पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सागरपाली), सेतकुमार पटेल चंद्रप्रकाश यादव, कान्ता पटेल, सुदामा साहू, प्रवीण चौहान, परमानंद नायक, केदार नायक, जयंत कुमार पटेल, गजेंद्र पटेल, चतुर्भुज यादव, भरत निषाद एवं सागरपाली के व्यवसायी लोकेशन अग्रवाल ने बताया कि, सड़क पर गड्ढों के कारण आए दिन यहाँ दुर्घटनाएँ होती रहती हैं, एवं दुर्घटिया वाहन चालक महिलाएँ भी आये दिन यहाँ गिरती रहती हैं, कईयों को चोटें आयी हैं। उन्होंने बताया कि, सड़क की समस्या को दूर करने लोक निर्माण विभाग भी किसी प्रकार की रूचि नहीं दिखा रही। बरसात में भारी वाहनों, गाड़ियों के आवागमन से रोड में गहरे गड्ढे बनते जा रहे हैं। लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। शिकायत करने पर विभाग द्वारा मखमल में टाट का पैन्थ की कहवात को चरितार्थ करते हुए कभी कभार मिट्टी डालकर खानापूर्ति कर दी जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों में स्थिति जस की तस हो जाती है। ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि लालचंद अग्रवाल ने बताया कि, रोड की समस्या का समाधान के लिए विभाग व विधायक को जानकारी दी गयी है। उन्होंने बताया कि, विभागीय अधिकारी ने बताया है कि, इस रोड का ठेका हो चुका है पर काम चालू नहीं किया गया है। सागरपाली के ग्रामीणों ने पुनः प्रशासन से इस ओर विशेष ध्यान देते हुए क्षेत्रवासियों को इस विकट परिस्थिति से राहत दिलाने की मांग शासन प्रशासन से की है। आग देखना है, पंचायत संजीवनी से पहल करते हुए इस समस्या के निराकरण के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर क्या उचित कदम उठाती है। जन मानस से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए क्या कुछ करती है। और विभाग कुंभकर्णी निद्रा से कब जागती है और कब इसकी सुध लेती है।

गुरु, इष्ट और स्वयं का जहां अपमान हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए -पंडित पुरन शर्मा

■ ग्राम छाटा में शिव महापुराण कथा का तीसरा दिन
■ सती चरित्र, दक्ष वध, पार्वती जन्म गुण निधि की कथा सुनाई

पाटन (समय दर्शन)। ग्राम छाटा में आयोजित शिव महापुराण कथा के तीसरा दिन गुरुवार को आचार्य पंडित पुरन प्रसाद शर्मा ने सती चरित्र, दक्ष वध, पार्वती जन्म गुण निधि की कथा सुनाई। संगीतमय भजन पर श्रोता झूमते रहे। कथा के तीसरा दिन आज सबसे पहले यादव परिवार द्वारा पूजा अर्चना किया गया। आचार्य पंडित पुरन शर्मा का



स्वागत सम्मान किया गया। व्यास पीठ से शिव महापुराण कथा का व्याख्यान करते हुए पंडित शर्मा ने कहा की किसी भी स्थान पर विना निमंत्रण जाने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जहां आप जा रहे हैं वहां आपका, अपने



इष्ट या अपने गुरु का अपमान हो या फिर यदि ऐसा होने की आशंका हो तो उस स्थान पर जाना नहीं चाहिए। चाहे वह स्थान अपने जन्म दाता पिता का ही घर क्यों हो। कथा के दौरान सती चरित्र के प्रसंग को सुनाते हुए भगवान शिव की बात को नहीं मानने पर सती के पिता के घर जाने से अपमानित होने के कारण स्वयं को अग्नि में स्वाह होना पड़ा। उन्होंने कहा कि दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी के पुत्र थे एवं माता सती के पिता थे और सती के पिता होने के नाते भगवान शिव के

ससुर भी हुए। दक्ष को माता सती का भगवान शिव से विवाह करना नहीं भाया, जिसके कारण उन्होंने विवाह के पश्चात अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। उन्होंने कहा की जब सती अपने आपको अग्नि के हवाले किया तब भगवान शिव ने उन्मत्त की भाँति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया। धरती पर जिन इक्यावन स्थानों में सती के अंग काट-कटकर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्तिपीठ माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था शिव और सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर और वंदनीय बना दिया इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

सरस्वती शिशु मंदिर मे विद्यार्थियों का शपथ ग्रहण समारोह



बसना (समय दर्शन)। सरस्वती शिशु मंदिर बसना में बोते दिन विद्यालय के अध्यक्ष रामचंद्र अग्रवाल सह सचिव रमेश कर एवं पूर्व छात्र दयानंद होता शिशु रोग विशेषज्ञ की उपस्थिति में शिशु भारती बाल भारती, कन्या भारती एवं किशोर भारती के नवनिर्वाचित पदाधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया।

सभी पदाधिकारियों को तिलक लगाकर सम्मानित किया गया। विद्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने तथा स्वयं में नेतृत्व क्षमता का विकास करने के लिए भैया बहनों को विभिन्न पद के दायित्व निर्वहन के लिए पूर्व छात्र दयानंद होता ने शपथ दिलावाई एवं आशीर्वचन के रूप में अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से निभाने के लिए प्रेरित किया। सह सचिव रमेश कर ने आशीर्वचन में कहा कि, बचपन से छोटी-छोटी जिम्मेदारी आती है तो आगे चलकर नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, अतः आज आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, उसे तन मन धन से निष्ठा पूर्वक पदाधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया।

ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल बनारी, जांजगीर में जीवन कौशल एवं कक्षा सजाओं गतिविधि आयोजित



जांजगीर-चांपा (समय दर्शन)। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, बनारी, जांजगीर में संस्था के संचालक श्री आलोक अग्रवाल एवं प्राचार्य श्रीमती सोनली सिंह के निर्देशानुसार दिनांक- 06/07/2024 को कक्षा- पहली से लेकर कक्षा-बारहवीं तक के विद्यार्थियों के लिए कक्षा सजाओं एवं जीवन कौशल गतिविधि आयोजित किया गया। कक्षा सजा गतिविधि के अंतर्गत विद्यार्थियों को अपनी-अपनी कक्षा में मुख्य रूप से बर्थडे चार्ट, बोर्ड डेकोरेशन एवं अन्य कक्षागत सजा को शामिल करना था। विद्यार्थियों द्वारा चार्ट पेपर, रंग एवं अन्य सजावटी साधनों के माध्यम से भिन्न-भिन्न प्रकार की कलाकृति का प्रदर्शन करते हुए अपनी-अपनी कक्षा को मन-मोहक दृश से सजाया गया। बच्चे अपनी कक्षा को सजाने के लिए उत्साहित नजर आए। साथ ही साथ कक्षा- पहली से कक्षा-बारहवीं तक के विद्यार्थियों को जीवन कौशल पर आधारित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया गया। कक्षा शिक्षक-शिक्षिकाओं द्वारा अपनी-अपनी कक्षा में अलग-अलग जीवन कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों को जागरूक किया। इन कौशलों के द्वारा विद्यार्थियों ने अपनी रोज मरा की विभिन्न जरूरी कार्यों को सीखा। इन कार्यों में मुख्य रूप से सुई धागा टंकन कला, टाई बांधना, जूते का लेस बांधना एवं अन्य दिनचर्या की गतिविधियों को शामिल किया गया। भिन्न-भिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने लाभ उठाया। इन गतिविधियों के सफल संचालन में संस्था के समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं, एडमिन स्टॉफ एवं ग्राउंड लेवल स्टॉफ का विशेष योगदान रहा।